



"जो प्राप्त है, वही पर्याप्त है, इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है।"

हवा में बना अभेद्य सुरक्षा घेरा, क्वांटम कंप्यूटर भी होंगे फेल

भारत की 'वैदिक कवच' तकनीक ने रच दिया नया इतिहास!

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में ऐसी कामयाबी हासिल कर ली है जिसे कोई भी बड़े से बड़ा सुपरकंप्यूटर या हैकर भेद नहीं करेगा। दरअसल देश में पहली बार वायरलेस तरीके से 5.56 किलोमीटर की दूरी तक फ्री-स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्यूकेडी का सफल परीक्षण किया गया है। यह कारनामा क्यूएनयू लैब्स, बिसाग-एन और आआईटी गांधीनगर ने मिलकर किया है। आने वाले समय में जब क्वांटम कंप्यूटर्स के आगे लगभग सभी पासवर्ड और मौजूदा इंटरनेट सुरक्षा फौकी पड़ जाएगी, तो यह स्वदेशी तकनीक भारत के बैंकों,



तुरंत पता चल जाएगा कि किसी ने चोरी की कोशिश की

इस तकनीक की एक खासियत और है कि अगर कोई किसी तरह वायरलेस तरीके से भेजे जाने वाली की या चाबी तक पहुंच बनाता भी है, तो वह अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा चाबी भेजने और पाने वाले दोनों को तुरंत पता चल जाएगा कि किसी ने चोरी की कोशिश की है। क्यूकेडी यानी कि फ्री-स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से काम करती है और इसे विज्ञान में क्वांटम सुरक्षा कहते हैं, जिसे कभी चुराया या हैक नहीं किया जा सकता।

सेना और जरूरी डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकेगी। आसान भाषा में समझें, तो यह एक गुप्त चाबी बनाने जैसा है, जो दो लोगों के बीच वायरलेस तरीके से भेजी जाती है। उदाहरण के लिए आप कोई जानकारी बक्से में बंद करके किसी को भेजें और उस बक्से की चाबी को वायरलेस तरीके से दूसरे शख्स तक पहुंचाएं, तो कोई चाबी को हथिया नहीं पाएगा।

रात में हुआ 5.56 किमी का सफल परीक्षण

रिपोर्ट्स के मुताबिक (आई.एफ.), क्यूकेडी तकनीक के ट्रायल को 27-28 सितंबर की रात को बिसाग-एन और आईआईटी गांधीनगर के बीच हवा में लेजर बीम के जरिए किया गया। इसमें क्यूएनयू लैब्स के खास ट्रेकिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल हुआ। इस टेस्टिंग में एरर रेट यानी कि गलतियों की संभावना 5 फीसदी से भी कम रही। इसके साथ ही प्रति सेकंड 230 से 260 बिट्स की रफ्तार से सुरक्षित सिक्रेट कोड तैयार हुआ। इन कोड्स के जरिए स्टेट मैसेजेस को भेजा गया।

फिर घर-घर जाएंगे बीएलओ, होगा एसआईआर सत्यापन

शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक काम में लगाने से बढ़ी नाराजगी



कोलकाता (एजेंसी)। बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के तहत एक बार फिर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को घर-घर जाकर सत्यापन का काम करना पड़ सकता है। एसआईआर से पहले की मतदाता सूची और

मौजूदा सूची का मिलान करने के बाद छूटे मतदाताओं की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद बीएलओ संबंधित लोगों के घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का सत्यापन करेंगे। इस काम में स्कूल शिक्षकों को फिर बीएलओ के रूप

बीएलओ मंच ने भी जताया विरोध

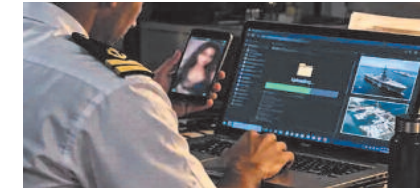
वोटकर्मी एवं बीएलओ मंच ने भी शिक्षकों को बार-बार गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाने पर नाराजगी जताई है। संगठन के महासचिव स्वप्न मंडल ने कहा कि शिक्षकों को लगातार स्कूल के मूल काम से अलग जिम्मेदारियां दी जाने का सीधा असर पढ़न-पाठन पर पड़ता है।

में लगाने की आशंका से शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही है। शिक्षकों का कहना है कि पिछले वर्ष नवंबर से एसआईआर का काम शुरू होने के बाद से ही कई स्तर पर पढ़ाई प्रभावित हुई। इसके बाद 2026 की शुरुआत में जांच हुई।

संक्षिप्त समाचार

पाकिस्तानी एजेंट के हनी ट्रैप में फंसा नेवी जवान
● खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप, कोयंबटूर से गिरफ्तार

कोयंबटूर (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश पुलिस की काउंटर इंटेलीजेंस सेल ने इंडियन नेवी के जवान प्रदीप मुखर्जी को कोयंबटूर से गिरफ्तार किया है। उस पर पाकिस्तानी महिला खुफिया एजेंट को डिफेंस की सेंसिटिव जानकारी देने का आरोप है।



टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंट ने जवान को हनीट्रैप में फंसाया था। प्रदीप कोयंबटूर के रेड फील्ड्स स्थित इंडियन नेवल शिप अग्रणी में मैनेजमेंट डेवलपमेंट कोर्स कर रहे थे। कुछ महीने पहले महिला एजेंट ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदीप से संपर्क किया था। उसने धीरे-धीरे उनसे दोस्ती बढ़ाई और विशाखापट्टनम नेवल बेस से जुड़ी जानकारी ली।

दीपावली से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार देगी तोहफा

● लाखों राज्यकर्मियों को मिलेगा बोनस और महंगाई भता

लखनऊ (एजेंसी)। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्यकर्मियों की दीपावली अधिक रोशन और रंगीन करने की तैयारी कर ली है। सरकार करीब 18 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दीपावली से पहले महंगाई भत्ता और बोनस का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है। सरकार के इस कदम से राज्यकर्मियों को बढ़ा हुआ डीए और बोनस 3400 से 7000 तक मिल सकता है। इसके साथ ही सरकारी कर्मियों और पेंशनरों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की भी तैयारी कर रही है।

सीईसी से जुड़े आत्महत्या मामले की होगी विजिलेंस जांच

● केरलम सरकार ने दिए आदेश 2006 में इंजीनियर ने की थी आत्महत्या

नई दिल्ली (एजेंसी)। केरलम गृह मंत्री रमेश चेन्नथला ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला 2006 में राज्य के लोक निर्माण विभाग के सचिव के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है। यह मामला मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या से जुड़ा है, जो केरल राज्य परिवहन परियोजना के तहत एमसी रोड के अपग्रेडेशन में शामिल कंसोर्टियम से जुड़े थे।



बीजेपी ने दो राज्यसभा उम्मीदवारों का किया ऐलान

● उत्तराखंड से दिनेश आर्य तो बंगाल से कोयल मल्लिक मैदान में

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को उत्तराखंड में 2026 के राज्यसभा (द्विवार्षिक) चुनाव के लिए दिनेश आर्य और पश्चिम बंगाल से रुक्मिणी मल्लिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तराखंड से मौजूदा राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल का कार्यकाल पूरा हो रहा है जिसके चलते उपचुनाव की जरूरत पड़ी। एक्ट्रेस से नेता बनीं रुक्मिणी मल्लिक, जिन्हें कोएल मल्लिक के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने इस साल जुलाई में तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिससे वह सीट खाली हुई। चुनाव आयोग ने 22 सितंबर को ऐलान किया था कि 16 अक्टूबर को 11 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव और बंगाल की एक सीट के लिए उपचुनाव होंगे।



इजराइली पीएम नेतन्याहू ने की भारतीय पायलट से बात

प्रधानमंत्री मोदी के साथ मशाल जलाने का दिया न्योता

तेल अवीव (एजेंसी)। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लाईटबूट एयरलाइन के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर से करीब 6 मिनट फोन पर बात की। उन्होंने कहा- आप भारत और इजराइल के लोगों के सच्चे हीरो हैं। आप पूरी दुनिया के हीरो हैं। नेतन्याहू ने स्मित को इजराइल आने का न्योता भी दिया। उन्होंने कहा- मैं आपको और अपने दोस्त पीएम मोदी को अगले स्वतंत्रता दिवस पर जश्न की मशाल जलाने का न्योता देना चाहता हूँ। नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित से पूछा कि फ्लाइट में आखिर हुआ क्या था। स्मित ने बताया कि हमले से पहले को-पायलट ने नमाज करने की बात कही।



घायल होने के बावजूद बहादुरी से किया संघर्ष

कॉकपिट के फर्श पर खून से लथपथ पड़े कैप्टन स्मित को तेज हवाओं की आवाजें और यात्रियों की चीखें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने खुद से कहा कि अगर वे इस आखिरी वक़्त में हिम्मत नहीं जुटा पाए, तो उनकी और विमान में मौजूद सभी लोगों की जान चली जाएगी। बची हुई पूरी ताकत झोंककर वे उठे, हर बाधा से लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे और उसे खोल दिया।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उद्भव-राज ठाकरे का हल्लाबोल

मुंबई में किया प्रदर्शन, बोले-सीईसी बीजेपी का हथियार हैं

मुंबई (एजेंसी)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रविवार को मुंबई में उद्भव ठाकरे और राज ठाकरे ने जॉइंट प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। दोनों नेताओं ने मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर महानगरपालिका भवन तक मार्च निकाला। उद्भव की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में हुए एसआईआर को रद्द किया जाए। सरकार किसकी बनेगी, ये फैसला जनता को तय करना है, चुनाव आयोग को नहीं। वहीं उद्भव बोले कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी का हथियार हैं।



‘तानाशाही तो हिटलर की भी नहीं चली’

उद्भव ठाकरे ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में इस वक़्त तानाशाही चल रही है, लेकिन यह सरकार ध्यान रखे कि हिटलर भी ऐसा ही एक तानाशाह था, लेकिन आखिर में उसे खुद को ही गोली मारनी पड़ी। इस देश में भी ऐसी ही स्थिति पैदा हो सकती है। जो लोग मनमानी कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

यहां तानाशाह को उखाड़ फेंकने के लिए आए हैं

उद्भव ठाकरे ने आगे कहा कि हम सभी आज यहां पर तानाशाह को ही उखाड़ फेंकने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश में 13 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। बंगाल और तमिलनाडु में भी वोटर्स को बाहर किया गया है। बंगाल में अभी भी उपचुनाव चल रहा है और लोगों ने वोट देने का अधिकार पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस दौरान उद्भव ठाकरे ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिशनरों के अपॉइंटमेंट पर मेरे मन में सवाल है।

बिहार एमएलसी चुनाव

महागठबंधन में हो रही फ्रेंडली फाइट तो जेडीयू में अंतर्कलह

पटना (एजेंसी)। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन या विपक्षी दल भले ही एकजुट नजर आ रहे हों, लेकिन बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की तस्वीर अलग दिखाई दे रही है। बिहार



विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव में राजद और कांग्रेस के उम्मीदवार कई सीटों पर आमने-सामने हैं। वहीं, जन सुराज ने सभी आठ सीटों पर उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। बिहार विधान परिषद की चार ख़ातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को होगी। एनडीए ने अपने हिस्से की चार-चार सीटें भाजपा और जयपू के बीच बांटी हैं।

नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की 'फाइनल' चार्जशीट जल्द

एनटीए अधिकारियों का नाम नहीं होगा शामिल, 13 निजी व्यक्ति हैं आरोपी



नई दिल्ली (एजेंसी)। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (सीबीआई) एक हफ्ते के अंदर नेशनल एलिजिबिलिटी कम प्रॉसेस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट 2026 पेपर लीक मामले में अपनी दूसरी और आखिरी चार्जशीट दाखिल करने वाली है लेकिन इसमें केंद्र सरकार या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के किसी अधिकारी को

चार्जशीट में 13 आरोपियों के नाम किए हैं शामिल

पेपर लीक मामले में पहली चार्जशीट 28 जुलाई को दाखिल की गई, जिसमें 13 आरोपियों के नाम शामिल हैं। इनमें एनटीए द्वारा नियुक्त तीन विषय विशेषज्ञ भी हैं बॉटनी और जूलॉजी के लिए मनीषा गुरुनाथ मधारे, केमिस्ट्री के लिए प्रह्लाद विट्टलराव कुलकर्णी और फिजिक्स के लिए मनीषा संजय हवलदार। सीबीआई ने तब कहा था कि उसने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ वेशचन्द्र डॉक्यूमेंट्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स की राय वाली रिपोर्ट जमा करने के लिए दूसरे साजिशकर्ताओं की भूमिका की जांच खुली रखी थी।

रूस ने ड्रेन से निशाना बनाया, 1 की मौत 400 करोड़ का नुकसान

यूक्रेन में भारतीय कारोबारी की फार्मा फैक्ट्री पर हमला

कीव (एजेंसी)। रूस ने यूक्रेन के सूभी शहर में भारतीय कारोबारी राजीव गुप्ता की दवा बनाने वाली फैक्ट्री पर ड्रेन से हमला किया। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। फैक्ट्री की मुख्य इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और इसका ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, कंपनी को कम से कम 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हमले के बाद फैक्ट्री वाले इलाके से धुएँ का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। अधिकारियों ने



पहले दूसरी कंपनियों की दवाएं बेचती थी कंपनी 2002 में कुसुम ग्रुप ने दूसरी कंपनियों की दवाएं बेचने का काम बंद कर दिया और अपने ब्रांड की दवाओं की मार्केटिंग शुरू की। इसके बाद कंपनी ने खुद दवाएं बनाना शुरू किया। 2007 में भारत में प्लांट शुरू किया गया। 2009 में यूक्रेन के सूभी में दवा बनाने की फैक्ट्री शुरू की गई।



सेक्टर-51 और 52 मेट्रो स्टेशन के बीच स्काईवॉक शुरू, सड़क पर उतरे बिना कर सकेंगे इंटरचेंज

रोजाना 20 हजार से अधिक यात्रियों को मिलेगी राहत

नोएडा। सेक्टर-51 स्थित नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) और सेक्टर-52 स्थित दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) स्टेशन के बीच बहुप्रतीक्षित स्काईवॉक रविवार से यात्रियों के लिए शुरू हो गया। करीब 460 मीटर लंबे इस स्काईवॉक से दोनों मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटरचेंज करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब यात्रियों को सड़क पर उतरे बिना एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने की सुविधा मिल गई है। नोएडा विधायक पंकज सिंह ने स्काईवॉक का औपचारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ स्काईवॉक पर पैदल चलकर व्यवस्थाओं का



जायजा लिया। अधिकारियों ने उन्हें यात्रियों की सुविधा और परियोजना से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। स्काईवॉक शुरू होने से रोजाना 20 हजार से अधिक यात्रियों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे खासतौर पर उन यात्रियों को सुविधा होगी, जिन्हें एनएमआरसी और

डीएमआरसी की मेट्रो सेवाओं के बीच इंटरचेंज करना पड़ता है। अब यात्रियों को सड़क पार करने और भारी यातायात के बीच से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। इससे समय की बचत के साथ सुरक्षा भी बढ़ेगी।

37 करोड़ रुपये की लागत से हुआ निर्माण

करीब 37 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए इस स्काईवॉक का उद्देश्य दोनों मेट्रो स्टेशनों के बीच सुरक्षित और सुगम पैदल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। दोनों स्टेशनों के बीच इंटरचेंज को लेकर यात्रियों को लंबे समय से सड़क पार करने और पैदल आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता था। स्काईवॉक शुरू होने के बाद इस समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक, यह परियोजना नोएडा में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे दिल्ली और नोएडा के मेट्रो नेटवर्क के बीच यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम होगी और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा।

संक्षिप्त समाचार

जानलेवा हमले के पांच आरोपी बरी

ग्रेटर नोएडा। दादरी थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुए मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में जिला न्यायालय ने पांच आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने सुखवीर, उसके बेटों कपिल और अनिल एवं अन्य आरोपी भोलू उर्फ प्रशांत, सुरेन्द्र को सभी आरोपों से सदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार वादी विनोद ने 10 मई 2015 को दादरी थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह और उसका भाई एनसीआर रिपोर्ट दर्ज कराकर घर पहुंचे तो सुखवीर, कपिल, अनिल, रोहित, भोलू और सुरेन्द्र तमंचे लेकर आए और जान से मारने की नीयत से गोली चलाने लगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया था। अदालत ने माना कि घटना की तारीख को चोटें आई थीं, लेकिन यह अभियोजन साक्ष्य से स्थापित नहीं हुआ कि ये चोटें आरोपियों ने पहुंचाईं। ऐसे में कोर्ट ने आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए बरी करने का फैसला दिया है।

रामलीला के मंच से हरियाली और स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा

ग्रेटर नोएडा। श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा द्वारा सेक्टर साइट- चार के सेंट्रल पार्क में आयोजित होने वाली रामलीला के मंच से इस बार हरियाली और स्वच्छता का विशेष संदेश दिया जाएगा। पूरे परिसर को हरा- बरा बनाने के लिए घास और पौधे लगाए गए हैं। कमेटी द्वारा विजय महोत्सव-2026 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आयोजकों के मुताबिक भव्य मंच बनाने के साथ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए मेले में झूले लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। रामलीला मंचन 11 से 21 अक्तूबर तक किया जाएगा।

कमेटी के अध्यक्ष सरदार मनजीत सिंह ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। प्रवेश और निकास द्वार सहित सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वालेंटियर यानी स्वयंसेवक और सिक्वोरिटी गार्ड की तैनाती की जाएगी। पुलिस का भी सहयोग मांगा गया है। आयोजन को भव्य बनाने के लिए इस बार पूरे रामलीला मैदान में सजावटी लाइट लगाने का काम चल रहा है। सरदार मनजीत सिंह ने बताया कि रामलीला मंच से हरियाली और स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। कमेटी द्वारा पूरे सेंट्रल पार्क में घास लगाई गई है। इसके साथ ही 500 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। बगते प्रदूषण को देखते हुए हरियाली पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

लापता किशोरी के मामले में देरी से मुकदमा दर्ज करने का आरोप

नोएडा। फेज-दो थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी 22 दिन से लापता है। [रिजन ने पड़ोस में रहने वाले तीन युवकों पर दुष्कर्म कर गंभवी करने, बहला-फुसलाकर ले जाने और पुलिस पर देरी से मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। पीड़ित पिता ने किशोरी के जल्द बरामद नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। महोबा के रहने वाले व्यक्ति परिवार संग फेज-दो थाना क्षेत्र के एक गांव में रहते हैं। वह सिक्वोरिटी गार्ड का काम करते हैं। उनकी 16 वर्षीय बेटी की 23 अगस्त को तबीयत खराब हुई थी। उपचार कराने पर पता चला था कि बेटी दो माह की गंभवी है।

व्यक्ति का आरोप है कि पड़ोस में रहने सुमित और राहुल नाम के दो युवकों ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया था। आरोप है कि फेज-दो थाना पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस टरकाती रही। बदलकर मने ही रहने का दबाव बनाया गया इसी बीच 13 सितंबर को सभी आरोपी मिलकर उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गए। दोनों का साथ पड़ोस में ही रहने गोंडा नाम के युवक ने भी दिया। उसके बाद भी पुलिस कई दिन तक टरकाती रही। 22 सितंबर को अपहरण और पाँसों की धारा में मामला दर्ज किया। उन्होंने बेटी के साथ अनहोनी होने के आशंका जताई है। किशोरी के पिता ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके पुलिस से जल्द से जल्द बेटी को खोजने की गुहार लगाई है। ऐसा न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। पुलिस का कहना है किशोरी के पिता की शिकायत पर मुकदमा कर किशोरी को खोजने के लिए टीमें गठित हैं।

सेक्टरपी-3 में लोगों के घरों तक पहुंच रहा गंदा पेयजल

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पी-3 में शनिवार रात से घरों में काले और मटमैले रंग के गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। पानी में मिट्टी की मात्रा इतनी अधिक है कि इसे देखकर लोग इस्तेमाल करने से भी डर रहे हैं। इसके बावजूद लगातार शिकायतों के बाद भी प्राधिकरण के अधिकारी समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं हैं। जब लोगों ने दोबारा रसोई में पानी की टंकियों और नलों को खोला तो फिर से काले रंग का बदबूदार पानी आया। इससे लोगों में नाराजगी है। सेक्टरवासियों का कहना है कि पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी उन्हें लगातार परेशान होना पड़ रहा है।

रात से गंदे पानी की आपूर्ति शुरू हुई थी। उम्मीद थी कि रविवार सुबह तक प्राधिकरण के अधिकारी समस्या को ठीक करा देंगे, लेकिन सुबह भी वही हालात बने रहे। घरों में आने वाले पानी में मिट्टी और गंगीय साफ दिखाई दे रही है। पानी से तेज बदबू भी आ रही है। ऐसे में लोग न तो इस पानी का सेवन कर सकते हैं और न ही घरेलू कामों में इसका इस्तेमाल करने की इच्छा में हैं। सेक्टर निवासी आदित्य भाटी ने बताया कि इस तरह के दूषित पानी का सेवन करने से लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। इससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियां होने का खतरा है। लगातार प्राधिकरण में शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले भी सेक्टर में इसी तरह गंदे पानी की आपूर्ति हुई थी। इसके बावजूद अधिकारियों ने समस्या का स्थायी समाधान नहीं कराया।

नोएडा को मिलेगा नया पिकनिक स्पाट, इसी माह खुलेगा जापानी पार्क

नोएडा। शहरवासियों को जल्द ही घूमने-फिरने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए नया पिकनिक स्पाट मिलने जा रहा है। सेक्टर-94 में करीब नौ एकड़ क्षेत्रफल में तैयार किया जा रहा जापानी पार्क इसी महीने लोगों के लिए खोले जाने की तैयारी है। करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जा रहे इस पार्क में जापानी संस्कृति, प्रकृति और शांति की झलक देखने को मिलेगी।

पार्क में जापानी थीम पर कई आकर्षण तैयार किए गए हैं। यहां जापानी झूले, ड्रैगन के आकार का झूला, सेल्फी वॉइंट, वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक, झरने और छोटे पुल बनाए गए हैं। बच्चों के लिए खेल का मैदान भी तैयार किया गया है। पार्क में दो वाटर बॉडी होंगी, जिनमें से एक के ऊपर से फुटपाथ बनाया गया है।



पार्क में जापानी गजीबो और जेन गार्डन भी विकसित किया गया है। जेन गार्डन जापानी शैली का पारंपरिक उद्यान है, जिसे शांति, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा पार्क में मियावाकी तकनीक से पौधे भी लगाए जाएंगे।

प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक पार्क की चारदीवारी, पाथवे, जल क्षेत्र और मुख्य प्रवेश द्वार से जुड़े कई काम पूरे हो चुके हैं। फिलहाल कुछ अंतिम कार्य किए जा रहे हैं। काम पूरा होने के बाद अक्टूबर में ही पार्क को आम लोगों के लिए खोलने की

अशोक सिंघल का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत : सुनील शर्मा

गाजियाबाद। कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि अशोक सिंघल देश के युवाओं के प्रेरणापुरुष थे। युवाओं को उनके जीवन, विचारों और राष्ट्र-समाज के प्रति समर्पण से प्रेरणा लेनी चाहिए। वह शनिवार को सरस्वती विद्या मंदिर, नेहरू नगर में विश्व हिंदू परिषद गाजियाबाद की ओर से आयोजित अशोक सिंघल जन्मशताब्दी वर्ष के उद्घाटन समारोह एवं हिंदू युवा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना, हिंदू समाज के संगठन और श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सांस्कृतिक पुनरुत्थान और समाज को संगठित करने में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। मुख्य वक्ता विहिप के अखिल भारतीय धर्माचार्य संपर्क प्रमुख अशोक तिवारी ने कहा कि अशोक सिंघल के व्यक्तित्व में दृढ़ विचार और संवेदनशीलता का अद्भुत संगम था।

बजरंग रामलीला संचालिका समिति ने निकाली भव्य शोभा यात्रा

नोएडा। नोएडा के सेक्टर 12 स्थित आदर्श प्राथमिक विद्यालय में श्री बजरंग रामलीला संचालिका द्रष्टृ द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालु दोलन-नागाड़ी और डीजे की धुन पर झूमते हुए नजर आए। इस शोभा यात्रा पर भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और रावण समेत विभिन्न प्रकार की झांकियां निकाली गईं। समिति के वरिष्ठ मुख्य संरक्षक राधा कृष्ण गर्ग, मुख्य संरक्षक शिवलाल सिंह, वरिष्ठ संरक्षक सुभाष चंद्र गौगना, नोफा के महासचिव सुरोजित दास गुप्ता, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुकेश यादव, ललित अवाना, पुरुषोत्तम नागर, दयाशंकर पाण्डेय, एवरग्रीन आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष और भाजपा नेता पुनीत शुक्ला, डीडीआरडब्ल्यूए के अध्यक्ष एनपी सिंह, डीडीआरडब्ल्यूए के महासचिव राजेश कुमार, पसमादंग मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान, वरिष्ठ समाजसेवी विक्रम सेठी, वरिष्ठ समाजसेवी मनोज बुजवास और कांग्रेस नेता राहुल पांडेय बसेरत कई रंग मान्य व्यक्तियों द्वारा झांकियों में विराजमान सभी पात्रों का भव्य स्वागत किया गया।

शोभा यात्रा सेक्टर 12 के आदर्श



प्राथमिक विद्यालय के रामलीला मैदान से निकाली गई। इसके बाद सेक्टर 12, सेक्टर 11, स्वामी फनीचर, सेक्टर 8, 9, बांस बल्ली, सेक्टर 19 टेलीफोन एक्सचेंज, सेक्टर 21, सेक्टर 10 की लाल बत्ती और चौड़ा मोड़ से होते हुए सेक्टर 12 के आदर्श प्राथमिक विद्यालय के रामलीला मैदान पर जाकर समाप्त हुई। सेक्टर 12 स्थित आदर्श प्राथमिक विद्यालय में आयोजित होने वाली बजरंग रामलीला संचालिका द्रष्टृ का शहर के विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय कलाकारों द्वारा निभाई जाएगी रामलीला में मुख्य

गाजियाबाद में होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर आयोजित

पुलिसकर्मियों समेत कुल 54 मरीजों को निशुल्क परामर्श और दवाएं दी गईं

गाजियाबाद। गाजियाबाद की रिजर्व पुलिस लाइन में रविवार को होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों समेत कुल 54 मरीजों को निशुल्क चिकित्सा परामर्श और दवाएं दी गईं। इनमें 27 पुरुष और 27 महिलाएं शामिल रहीं।

शिविर का आयोजन वामा साथी के सहयोग से आयुष विभाग के होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग ने किया। चिकित्सकों के अनुसार शिविर में 28 मरीज तीव्र बीमारियों और 26 मरीज पुरानी या गंभीर बीमारियों से पीड़ित पाए गए। सभी मरीजों की जांच के बाद बीमारी के अनुसार दवाएं दी गईं और स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सलाह भी दी गई। शिविर में सदी-खांसी, एलर्जी, त्वचा संबंधी बीमारी, बदहजमी, दस्त, मधुमेह, गठिया, पथरी, मुंह के छाले और माइग्रेन जैसी समस्याओं से पीड़ित मरीज पहुंचे। चिकित्सकों ने मरीजों को खान-पान और दिनचर्या में सावधानी बरतने की सलाह दी। मधुमेह के मरीजों को नियमित व्यायाम और शुगर की जांच कराने की



सलाह दी गई। शिविर में प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. रश्मि ओझा, फार्मासिस्ट

शैलेष गुप्ता, कर्मचारी नदीम और नोडल अधिकारी डॉ. उषा शेरवाल समेत अन्य लोगों ने सेवाएं दीं।

मैराथन फॉर हेल्थ में दौड़े डेढ़ हजार लोग, स्वस्थ एवं सक्रिय रहने का दिया संदेश

गाजियाबाद, गुलशन भारती। जीटी रोड स्थित ऑपुलेंट मॉल से मैराथन फॉर हेल्थ 2.0 दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौड़ में फिटनेस प्रेमियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। करीब डेढ़ हजार से अधिक युवाओं, विद्यार्थियों ने अपने परिजनों के साथ दौड़ लगाकर स्वस्थ एवं सक्रिय रहने का संदेश दिया। दौड़ का आयोजन नई उमंग और नई प्रगति नई पहल संस्थाओं ने संयुक्त रूप से किया। इस्कोन मंदिर के स्वामी दयालु प्रभु ने सुबह पांच बजे ध्वाजरोहण के मैराथन का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने विजेताओं को पुरस्कार देकर कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए फिटनेस को जीवनशैली बनाना जरूरी है। उन्होंने युवाओं से खेल, व्यायाम और अनुशासित जीवनशैली को अपनाने का आह्वान किया। संस्था के अध्यक्ष अनुज

त्यागी और कोषाध्यक्ष राहुल गोयल ने कहा कि इसका उद्देश्य स्वास्थ्य को जनआंदोलन और फिटनेस को जीवनशैली बनाने का संदेश घर-घर तक पहुंचाना है। इस मौके पर अमित गुप्ता, मोहित जैन, खुशबू चौधरी, अजय गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। मैराथन में राष्ट्रीय सैनिक संस्था से खेल प्रशिक्षण ले रही 13 साल की बालिका ज्योति कुमारी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस पर उन्हें ट्रॉफी और 1500 रुपये नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था की स्पोर्ट्स विंग जिला अध्यक्ष स्वाति बंसल और महासचिव मोनिका कश्यप पिछले चार महीने से गरीब बच्चों को प्रतिदिन मॉडल टाउन ईस्ट के सार्वजनिक पार्क में निशुल्क शारीरिक एक्टिविटी एवं शैक्षिक प्रशिक्षण दे रही हैं, ताकि कमजोर वर्ग के बच्चे आत्म सम्मान और आत्म विश्वास के साथ जीवन यापन कर सकें

निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर तीन लोगों से 52 लाख की टगी

दो अन्य लोगों को भी बनाया निशाना

नोएडा। ऑनलाइन निवेश में मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर साइबर ठगों ने तीन लोगों से करीब 52 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने पीड़ितों को निवेश पर अच्छे लाभ का भरोसा दिलाया था। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस लेनदेन से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी का पहला मामला 27 वर्षीय कारोबारी अनिश शर्मा का है।

वह बिसरख थाना क्षेत्र की आरमपाली लेजर वैली सोसाइटी में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 30 अप्रैल 2026 को व्हाट्सएप के माध्यम से उनकी बातचीत निधि नाम की महिला से शुरू हुई। महिला ने शेयर बाजार से

संबंधित जानकारी देने और निवेश में अच्छा मुनाफा कमाने का दावा किया। शुरूआत में अनिश ने उसके बताए कुछ सौदे अपने ब्रोकर खाते से किए, जिनमें उन्हें लाभ हुआ। इससे उनका भरोसा बढ़ गया इसके बाद महिला ने अनिश की बातचीत अनुराग नाम के व्यक्ति कराई। अनुराग ने खुद को निवेश का संचालन करने वाला बताया और दूसरे लोगों के निवेश का प्रबंधन करने का दावा किया। उसकी बातों में आकर अनिश ने छोटी-छोटी रकम निवेश करनी शुरू कर दी। उन्हें लाभ के रक्रीनशॉट दिखाए गए और ज्यादा रकम लगाने पर अधिक मुनाफे का लालच दिया गया। 30 अप्रैल से एक जुलाई 2026 के बीच उन्होंने 28 लेनदेन में अलग-अलग बैंक खातों और यूपीआई आईडी पर कुल 29 लाख 61 हजार

994 रुपये ट्रांसफर किए। रकम वापस मांगने पर आरोपी लालमटोल करने लगे। कई बार भुगतान का आश्वासन देने के बावजूद पूरी रकम वापस नहीं मिली। अनिश ने राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब मामला साइबर क्राइम थाने में दर्ज हुआ है। दूसरे मामले में हरेश बिहारी जोहरी ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में 11 लाख 36 हजार 700 रुपये गंवाने की शिकायत की है। वह दादरी में रहते हैं। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने किसी अन्य व्यक्ति के रूप में खुद को पेश कर उन्हें झांसे में लिया और रुपये ट्रांसफर करा लिए। तीसरे मामले में सेक्टर 76 निवासी आनंद कुमार सिंह ने 11 लाख 11 हजार 500 रुपये की ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज कराई है।

सैनिकों के अपमान की पोस्ट से नाराज पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया

ट्रांस हिंडन। इंदिरापुरम में सोशल मीडिया पर सैनिकों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो के विरोध में रविवार को पूर्व सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों के जवानों और स्थानीय निवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान में बनेर हाथों में लेकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने पोस्ट हटाने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सैनिकों ने बताया कि सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में सैनिकों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इसमें कथित तौर पर सैनिकों के अधिकारियों के घरों में घरेलू काम करने और कुत्ते घुमाने जैसी बातें कही गई हैं। प्रदर्शन में शामिल नेवी से रिटायर्ड शमशेर सिंह सरदार ने कहा कि एक महिला ने सोशल मीडिया पर सैनिकों और सैन्य अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। ऐसी टिप्पणियों

से सैनिकों और उनके परिवारों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने इसे सैनिकों के सम्मान के खिलाफ बताया। वहीं प्रदर्शन में शामिल बलवंत सिंह ने बताया कि सैनिकों का अपमान नहीं सहा जाएगा। उन्होंने कहा कि सैनिक हिंदुस्तान की शान हैं और ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया से हटाई जाए। स्थानीय पार्षद हरीश कड़ाकोटी ने बताया कि पूर्व सैनिकों और स्थानीय निवासियों ने जिलाधिकारी के नाम शिकायती ज्ञापन तैयार किया है। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो हटवाए और मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है। प्रदर्शन में पार्षद हरीश कड़ाकोटी, पूर्व सुबेदार बलवंत सिंह, डीएस नेगी कमांडो, असिस्टेंट कमांडेंट सोबन सिंह, कैप्टन मोहन चंद्र भट्ट, एसपी ढोंडियाल, कैप्टन प्रहलाद सिंह सहित कई पूर्व सैनिक और स्थानीय निवासी मौजूद रहे।

किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की बैठक में आंदोलन की रणनीति पर हुआ मंथन

ग्रेटर नोएडा। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला कार्यकारिणी की बैठक कार्यालय, चाई फोर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ज्ञान सिंह भगवान ने की तथा संचालन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लोकेश भाटी ने किया। बैठक में किसानों, मजदूरों, युवाओं तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की विभिन्न मूलभूत समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

संगठन के राष्ट्रीय महासचिव आलोक नागर एवं प्रवक्ता बृजेश भाटी ने बताया कि संगठन द्वारा आने वाले दिनों में गौतमबुद्ध नगर जिले की तीनों तहसीलों पर प्रदर्शन कर किसानों और मजदूरों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ विकास प्रधान ने कहा कि किसानों से जुड़े 64 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा, 4 प्रतिशत आबादी भूखंड, बैंक लीज सहित अन्य लंबित समस्याओं के समाधान के लिए संगठन मजबूती



से आवाज उठाएगा। इसके साथ ही युवाओं के रोजगार तथा अन्य जनसमस्याओं को लेकर जिले

की तीनों तहसीलों एवं चारों प्राधिकरणों के स्तर पर बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बैठक में संगठन के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई और आगामी दिनों में गांव-गांव तथा क्षेत्रवार संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर डॉक्टर विकास प्रधान, आलोक नागर, बृजेश भाटी, रविंद्र प्रधान, लोकेश भाटी योगेंद्र मावी, नरेंद्र भाटी, ओमवीर बीडीसी, नासिर प्रधान राजकुमार रूपवास, संदीप चंदीला शुभम चेची, मनीष नागर, नीटू गुर्जर अरुण प्रधान सरोज भाटी, विनोद मलिक, हिमांशु तवर, प्रेम सिंह नगर, सरजीत प्रधान विनोद शर्मा गौरव भाटी, शिवम भाटी ठाकुर सीपी सोलंकी लीलू गुरुजी मनोज, भगत जी, श्रीकांत नागर, राजकुमार जेवर, कल्लू पारसोल, जाहिर खान, अजय पाल यादव, राशिद जेवर, काफी संख्या में लोग मौजूद रहे

मुख्य चुनाव आयुक्त क इस्ताफ का माग का लेकर सड़का पर उतरे सपा कार्यकर्ता, पुलिस से झड़प के बाद फूँका पुतला

हापुड़। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ की मांग को लेकर रविवार को जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसील चौराहे और सपा कार्यालय के पास कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूँका। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी हुई।

प्रदर्शनकारी सपा नेताओं ने निर्वाचन आयोग पर निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाने का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ की मांग की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और फर्जी वोटों के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग की भूमिका सवालियों के घेरे में है। पुतला दहन और प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने



कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के चलते इलाके में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

संक्षिप्त समाचार

बालकनी से छलांग, फिर घर की गहरी खाई में कूदी महिला, पुलिस-दमकल ने बचाई दो जिंदगियां



नई दिल्ली। एक तरफ पहली मंजिल की बालकनी से छलांग, दूसरी तरफ घर की गहरी खाई में जंझी और मौत के बीच जुझती महिला दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जैतपुर एक्सटेंशन में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस को एक महिला के कमरे में खुद को बंद करने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही कालिंदी कुंज थाना पुलिस ने बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू कर दिया। साउथ ईस्ट डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि मिली सूचना पर थाना कालिंदी कुंज के एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस टीम डी-ब्लॉक जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-2 पहुंची। वहां करीब 25 वर्षीय महिला घायल अवस्था में मिली। आरोप है कि उसने पहली मंजिल की बालकनी से सड़क की ओर छलांग लगा दी थी। पुलिस ने तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। इसी दौरान करीब 24 वर्षीय फातिमा (परिवर्तित नाम) ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दमकल कर्मियों की मदद से कमरा खोला गया तो वह घर की शाफ्ट में कूद चुकी थी। इसके बाद पुलिस और दमकल की टीम ने जोखिम उठाते हुए संयुक्त बचाव अभियान चलाया और फातिमा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रारंभिक जांच में दोनों के ननद-भाभी होने की बात सामने आई है। कथित वीडियो को लेकर विवाद के बाद दोनों ने यह कदम उठाया। दोनों महिलाओं को उपचार के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर भेज गया।

बंद सिनेमाघरों में फिर गुंजेगा पर्दे का शोर सिंगल स्क्रीन बचाने की उठी आवाज, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से नई नीति लाने की मांग



नई दिल्ली। कभी दिल्ली के मोहल्लों में सिनेमा का पर्दा उठते ही दर्शकों के चेहरे खिल उठते थे। टिकट सस्ता होता था मनोरंजन घर के करीब होता था और हर सप्ताह सिनेमा हॉल के बाहर मानो मेले जैसा नजारा दिखाई देता था। लेकिन वक्त बदला मल्टीप्लेक्स संस्कृति आई और देखते ही देखते दिल्ली के सैकड़ों सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों पर ताले लटक गए। अब इन बंद पड़े सिनेमाघरों को फिर से जीवंत करने की मांग उठी है। दिल्ली सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर दशक मंच के संयोजक एवं शिक्षाविद् डॉ. दयानंद वत्स भारतीय ने मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता से दिल्ली में बंद पड़े सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों के जीर्णोद्धार और पुनः संचालन के लिए नई नीति बनाने की मांग की है। डॉ. वत्स ने कहा कि सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर आम और गरीब परिवारों के लिए सस्ते मनोरंजन का महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं। मल्टीप्लेक्स में बढ़ती टिकट दरों के कारण सामान्य परिवार के लिए फिल्म देखना महंगा हो गया है। उनका कहना है कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे लोगों को उनके घरों के आसपास किफायती मनोरंजन उपलब्ध हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर हादिल्ली सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर नीति लाने की दिशा में तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है।

डिजिटल गिरफ्तारी के जाल का पदार्पाश, दो आरोपी गिरफ्तार



नई दिल्ली। राजधानी में डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ दक्षिण जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साइबर दक्षिण थाना पुलिस ने छह लाख रुपये की ठगी के मामले में जम्मू-कश्मीर और राजस्थान से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान एक अन्य बैंक खाते में करीब 50 लाख रुपये के लेन-देन और अलग-अलग राज्यों की 10 साइबर शिकायतों से जुड़े होने का भी खुलासा हुआ है।

दक्षिण जिला डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि पीड़ित को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए कानून-प्रवर्तन एजेंसियों का अधिकारी बनकर डराया गया और कथित डिजिटल गिरफ्तारी का भय दिखाकर छह लाख रुपये अलग-अलग खातों में स्थानांतरित करा लिए गए। इस मामले में साइबर दक्षिण थाने में ई-एफआईआर संख्या 499/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। जांच में पता चला कि ठगी की रकम सबसे पहले राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी मुकेश कुमार के फेडरल बैंक खाते में पहुंची। इसके बाद पांच लाख 50 हजार रुपये जम्मू-कश्मीर के कटुआ निवासी रितिश कुमार मेहरा के कोटक महिंद्र बैंक खाते में भेजे गए। पुलिस ने वित्तीय लेन-देन की कड़ी जोड़ते हुए पहले रितिश और फिर मुकेश को गिरफ्तार कर लिया।

डाक के पार ड्रग्स का खेल बेनकाब अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा

नई दिल्ली/चंडीगढ़। विदेश से आने वाले डाक पार्सलों की आड़ में नशे का कारोबार चलाने वाले आरोपी पर कानून का शिकंजा कस गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की चंडीगढ़ जोनल यूनिट की प्रभावी जांच के बाद हिमाचल प्रदेश के सोलन निवासी पंकज शर्मा को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामला 4 जुलाई 2023 का है। एनसीबी को खुफिया सूचना मिली थी कि ब्रिटेन से आने वाले एक अंतरराष्ट्रीय डाक पार्सल में मादक पदार्थ छिपाकर भेजे जा रहे हैं। अनुमति लेकर एनसीबी ने नियंत्रित डिलीवरी अभियान चलाया। सोलन मुख्य डाकघर में पार्सल लेने पहुंचे पंकज शर्मा को मौके पर पकड़ लिया गया। पार्सल की जांच में 4.7 ग्राम कोकीन बरामद हुई। इसके बाद फ्रांस से आए दूसरे पार्सल की तलाशी में 56.2 ग्राम एमडीएमएम मिला, जो निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा से पांच गुना से भी अधिक था। जांच के दौरान जर्मनी से आरोपी के लिए भेजे गए तीसरे पार्सल का भी पता चला जिसमें 4.4 ग्राम कोकीन बरामद हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी यूरोप के अलग-अलग देशों से अंतरराष्ट्रीय



डाक माध्यम के जरिए मादक पदार्थ मंगाता था। अभियोजन ने डाक कर्मचारियों की गवाही, डिलीवरी दस्तावेज जबकी कार्रवाई और वैज्ञानिक साक्ष्यों के जरिए आरोपी का सचेत कब्जा साबित किया। 3 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायाधीश-द्वितीय सोलन ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22(सी) के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। एनसीबी ने नागरिकों से नशीले पदार्थों की तस्करी की सूचना मानस राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 पर देने की अपील की है।

हार्डटेंशन लाइन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत, वन विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद किया निस्तारण

जनपद हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के ग्राम मानिक चौक में हार्डटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत हो गई। तेंदुए का शव धान के खेत में मिलने से क्षेत्र में हलचल मच गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार उसका निस्तारण कर दिया। जानकारी के अनुसार, 3 अक्टूबर 2026 को शाम ग्राम मानिक चौक में मृत तेंदुआ मिलने की सूचना पर हापुड़ वन प्रभाग की गढ़मुक्तेश्वर रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी करन सिंह और डीएफओ गौतम सिंह वन कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान पता चला कि धान के खेत में खड़े शीशम के पेड़ के पास से 11 हजार वोल्ट की हार्डटेंशन विद्युत लाइन गुजर

रही थी। आशंका है कि पेड़ पर चढ़ने के दौरान तेंदुआ बिजली के तारों की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई और वह नीचे गिर गया।

वन विभाग की टीम ने मृत तेंदुए को बरामद कर रेंज कार्यालय पहुंचाया। रविवार, 4 अक्टूबर को आलमगौर पौधशाला परिसर में तीन पशु चिकित्सकों की टीम ने तेंदुए का पोस्टमार्टम किया। टीम में डॉ. नवनीत कुमार, डॉ. मदन पाल सिंह और डॉ. विशाल चौधरी शामिल रहे।

पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग ने नियमानुसार पौधशाला परिसर में ही तेंदुए के शव को जलाकर निस्तारित कर दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी लगातार उच्चाधिकारियों को दी जाती रही।

पंख स्वयंसेवी संस्था के क्रेच-कम-प्ले स्कूल में खुशियों और रचनात्मकता का संगम

नई दिल्ली। पंख स्वयंसेवी संस्था के क्रेच-कम-प्ले स्कूल में शनिवार का दिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए खुशियों, सहयोग, स्नेह और रचनात्मक गतिविधियों से भरा रहा। समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े शुभचिंतकों और स्वयंसेवकों ने बच्चों के साथ समय बिताकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखरी।

दो उत्साही युवा स्वयंसेविकाएं खुशी और भूमिका अपनी पहली नौकरी मिलने की खुशी बच्चों के साथ साझा करने के लिए क्रेच-कम-प्ले स्कूल पहुंचीं। उन्होंने अपनी उपलब्धि का जश्न बच्चों के साथ मनाते हुए उन्हें समोसे और शीतल पेय वितरित किए। बच्चों के साथ उनकी आत्मीय सहभागिता ने पूरे वातावरण को खुशनुमा बना दिया। इसी क्रम में रोहिणी के सेक्टर-3 निवासी शशि भूषण अपने परिवार के साथ संस्था पहुंचे। वे बच्चों और जरूरतमंद



परिवार के लिए अच्छी स्थिति में उपयोग किए जा चुके कपड़ों से भरे चार बड़े बैग लेकर आए। पंख संस्था के मानद सलाहकार अजय भाटिया ने इस सहयोग को कृतज्ञतापूर्वक

स्वीकार करते हुए शशि भूषण और उनके परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। दिन को रचनात्मकता से जोड़ते हुए राशि जैन अपनी बेटी आयरा जैन तथा भांजे विद्यान जैन के साथ क्रेच-

कम-प्ले स्कूल पहुंचीं। उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया और कला एवं शिल्प गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान बच्चों के बीच रंग भरने की पुस्तकें और रंग भी वितरित किए गए। इससे बच्चों को अपनी कल्पनाशक्ति और रचनात्मक प्रतिभा को अभिव्यक्त करने का अवसर मिला।

कार्यक्रम के अंत में तीनों अतिथि समूहों ने पंख संस्था की आगंतुक पुस्तिका में अपने अनुभव और बहुमूल्य सुझाव भी दर्ज किए। यह पूरा दिन पंख संस्था के मूल उद्देश्य-बच्चों के साथ खुशियां, संसाधन, शिक्षा, स्नेह और अवसर साझा करना-का सुंदर उदाहरण रहा। ऐसे छोटे-छोटे प्रयास बच्चों को केवल आवश्यक वस्तुओं का सहयोग ही नहीं देते, बल्कि उनमें अपनत्व, आत्मविश्वास और समाज के प्रति सकारात्मक विश्वास भी विकसित करते हैं।

भारतीय किसान यूनियन बाबा के कार्यालय पर सदस्यता अभियान का आयोजन, चौधरी इशरत अली को राष्ट्रीय छात्र सभा में मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

भारतीय किसान यूनियन बाबा के कार्यालय पर संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक किसानों एवं युवाओं को संगठन से जोड़ने के उद्देश्य से सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में लोगों को भारतीय किसान यूनियन बाबा की विचारधारा और किसान हितों के संघर्ष से अवगत कराया।

इसी अवसर पर चौधरी इशरत अली को भारतीय किसान यूनियन बाबा की राष्ट्रीय छात्र सभा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। संगठन ने उनके संघर्ष, सक्रियता और किसानों की समस्याओं को मजबूती से उठाने के प्रयासों को देखते हुए यह जिम्मेदारी दी है।

चौधरी इशरत अली लंबे समय से किसानों और आम लोगों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। वह किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने तथा उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास करते हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि चौधरी इशरत अली एक संघर्षशील किसान



नेता हैं, जो किसानों की आवाज को मजबूती से आगे रखने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। संगठन की ओर से अलीगढ़, बुलंदशहर, अमरोहा, मुरादाबाद, मेरठ, हापुड़,

गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर सहित अन्य जनपदों की कार्यकारिणियों में भी सदस्यता अभियान को गति देने का आह्वान किया गया। उद्देश्य है कि गांव-गांव और

जनपद-जनपद तक संगठन को मजबूत किया जाए तथा अधिक से अधिक किसानों, युवाओं और मेहनतकश लोगों को संगठन के साथ जोड़ा जाए।

इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन बाबा किसानों की समस्याओं, उनके अधिकारों और सम्मान की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। संगठन का प्रयास रहेगा कि किसानों की आवाज संबंधित अधिकारियों और सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए और जमीनी स्तर पर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष जारी रखा जाए।

चौधरी इशरत अली को नई जिम्मेदारी मिलने पर संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दीं। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व और सक्रिय भूमिका से राष्ट्रीय छात्र सभा को मजबूती मिलेगी तथा संगठन के सदस्यता अभियान को भी नई गति प्राप्त होगी।

भारतीय किसान यूनियन बाबा का संदेश स्पष्ट है कि किसान की आवाज को मजबूत करना है, संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाना है और किसानों के हितों के लिए संघर्ष को लगातार आगे बढ़ाना है।

संपादकीय

दे हफ़्तों में पवित्र शहरों पर दूसरा हमला: धार्मिक स्थलों पर हमलों को रोकने की तत्काल जरूरत



अनीता यादव

सऊदी अरब के पवित्र शहरों मक्का और मदीना को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमलों के बाद तनाव बढ़ गया है। सऊदी गठबंधन और ओआईसी ने इसके लिए हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया, हालांकि हूतियों ने इससे इनकार किया है। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत ऐसे पवित्र धार्मिक स्थलों पर हमला करना गंभीर युद्ध अपराध माना जाता है।

पवित्र धार्मिक शहरों पर दूसरा हमला, 2017 के बाद से सबसे गंभीर हमला, मंगलवार, 29 सितंबर 2026 को स्थानीय समयानुसार सुबह 5:11 बजे हुआ। हूतियों ने मदीना में तैबा पावर डिस्ट्रिब्यूशन स्टेशन को निशाना बनाया, जो इस्लाम के दूसरे सबसे पवित्र स्थल 'अल-मस्जिद अन-नबवी' को बिजली सप्लाई करने वाली एक नागरिक सुविधा है। एक वन-वे अटैक ड्रोन ने एक ट्रांसफॉर्मर को बेकार कर दिया। सऊदी गठबंधन ने बताया कि बड़े ग़्रिड पर कोई असर नहीं पड़ा और मस्जिद में बिजली गुल नहीं हुई। गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-माल्की ने पुष्टि की कि मलबे को बरामद कर लिया गया है और ऑपरेशनल रिव्यू से हूतियों की संलिप्तता की पुष्टि हुई है। दो हफ्ते पहले, मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को स्थानीय समयानुसार शाम 6:50 बजे, सऊदी अरब ने मक्का के दक्षिण में एक हूती ड्रोन को ग्रेड मस्जिद के ऊपर प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही रोककर नष्ट कर दिया। 2017 के बाद मक्का पर यह पहली कोशिश थी। सऊदी अधिकारियों ने इस हमले के लिए यमन के हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया; बढ़ते तनाव के बीच इस्लाम के सबसे पवित्र शहर पर यह अपनी तरह की पहली घटना थी। सऊदी एयर डिफेंस ने जेद्दा से लगभग 70 किलोमीटर अंदर ड्रोन को रोक दिया, जिससे वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया। सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल-मलिकी ने बताया कि मक्का के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ही ड्रोन को रोक दिया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि दो पवित्र मस्जिदों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा एक 'रेड लाइन' (अति-संवेदनशील सीमा) है। उन्होंने इस हमले की निंदा करते हुए इसे 'धार्मिक हक़रात' बताया, जिसका मकसद इबादत करने वालों में डर पैदा करना और आम नागरिकों को नुकसान पहुँचाना था।



प्रमोद पंत

अहिंसा की राजनीति के कार्यकर्ता भारत की राजनीति में युवा हमेशा से परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को केवल संख्या के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं है। इंटरनेट, सामाजिक माध्यमों, डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में पली-बढ़ी यह पीढ़ी राजनीति से भी संवाद की नई भाषा की अपेक्षा करती है।

आज का युवा केवल यह नहीं पूछता कि सरकार क्या देगी। वह यह भी पूछता है कि व्यवस्था कैसे काम करेगी, अवसर कैसे मिलेंगे और उसके भविष्य के फैसलों में उसकी अपनी भागीदारी कितनी होगी।

रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, प्रश्नपत्र लोक, शिक्षा की बढ़ती लागत और डिग्री के बाद रोजगार का सवाल आज लाखों युवाओं की चिंता का विषय है। इन सवालों के बीच राहुल गांधी की छात्रों की गुंज जैसी पहल को केवल राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसे युवाओं और राजनीति के बीच बदलते संवाद के संदर्भ में भी समझना होगा।

परंपरागत राजनीति में नेता बोलता था और जनता सुनती थी। आज स्थिति बदल चुकी है। नई पीढ़ी सवाल करती है, जवाब मांगती है और उपलब्ध जानकारी की अपने स्तर पर पड़ताली भी करती है। सामाजिक माध्यमों ने उसे अपनी बात रखने का ऐसा मंच



दिया है, जहाँ राजनीतिक दावों पर तत्काल प्रतिक्रिया संभव है।

यही कारण है कि युवाओं के बीच किसी भी राजनीतिक पहल की सफलता केवल भीड़ या नारों से तय नहीं होगी। असली कसौटी यह होगी कि युवाओं के सवालों को नीति और व्यवस्था में कितना स्थान मिलता है।

रोजगार सबसे बड़ा सवाल

आज की युवा पीढ़ी के सामने सबसे गंभीर प्रश्न रोजगार का है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार की अनिश्चितता चिंता पैदा करती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की लंबी प्रक्रिया, भर्ती में देरी और प्रश्नपत्र लोक जैसी घटनाएँ युवाओं के भरोसे को प्रभावित करती हैं।

किसी विद्यार्थी के लिए प्रश्नपत्र लोक केवल एक परीक्षा का संकेत नहीं होता। इसके पीछे वर्षों की मेहनत, परिवार का आर्थिक निवेश और भविष्य की योजनाएँ जुड़ी होती हैं। इसलिए परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और समयबद्ध भर्ती केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि युवा भविष्य से जुड़ा प्रश्न है।

राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर केवल आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर ठोस समाधान प्रस्तुत करने होंगे। परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित कैसे बनाया जाए, भर्ती प्रक्रिया की समयसीमा क्या हो और परीक्षा प्रभावित होने पर विद्यार्थियों के हितों की रक्षा कैसे की

जाए—इन सवालों के स्पष्ट उत्तर आवश्यक हैं डिग्री से आगे अवसर की तलाश

आज का युवा केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार का एकमात्र विकल्प नहीं मानता। निजी क्षेत्र, अपना व्यवसाय, स्वतंत्र कार्य, घर से काम, तकनीक आधारित रोजगार और रचनात्मक क्षेत्र भी उसके सामने अवसर के रूप में मौजूद हैं।

इस बदलती अर्थव्यवस्था को राजनीतिक विमर्श में पर्याप्त स्थान देना होगा। शिक्षा व्यवस्था को भी रोजगार बाजार में हो रहे बदलावों के अनुरूप तैयार करना होगा। केवल डिग्री देने वाली शिक्षा व्यवस्था युवाओं के आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। शिक्षा को कौशल, रोजगार और उद्यमिता से जोड़ना समय की आवश्यकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौती कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने रोजगार और अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। कुछ पारंपरिक कामों का स्वरूप बदल रहा है तो दूसरी ओर नए क्षेत्रों में अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल नौकरियाँ खत्म करेगी या नहीं। असली सवाल यह है कि भारत का युवा इस बदलाव के लिए कितना तैयार है।

क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था युवाओं को नई तकनीक के अनुरूप कौशल दे रही है? क्या छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के

युवाओं को भी समान अवसर मिलेंगे? क्या युवा केवल तकनीक का इस्तेमाल करेंगे या उसके विकास और निर्माण में भी भागीदार बनेंगे?

इन सवालों पर राजनीतिक दलों को गंभीरता से विचार करना होगा।

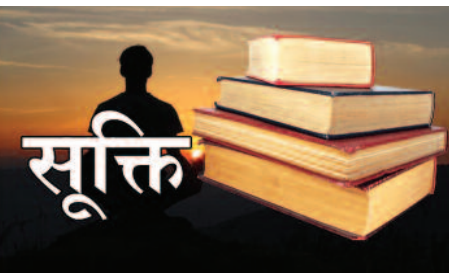
आंकड़ों की नई अर्थव्यवस्था डिजिटल युग में व्यक्ति का आंकड़ा भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन बन चुका है। इंटरनेट पर की गई खोज, खरीदारी, स्थान संबंधी जानकारी और सामाजिक माध्यमों पर गतिविधियाँ बड़ी मात्रा में डिजिटल आंकड़े पैदा करती हैं।

ऐसे में युवा पीढ़ी का यह सवाल स्वाभाविक है कि उसके आंकड़ों का उपयोग कौन करता है और उससे पैदा होने वाली आर्थिक शक्ति में उसकी भूमिका क्या है।

डिजिटल अधिकार, आंकड़ों की सुरक्षा और तकनीक से पैदा होने वाले आर्थिक अवसर आने वाले समय में राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दे बनने वाले हैं।

संवाद से आगे भागीदारी जरूरी राहुल गांधी और नई पीढ़ी के बीच संवाद की पहल का महत्व तभी बढ़ेगा जब वह संवाद केवल मंचों और कार्यक्रमों तक सीमित न रहे। युवाओं को राजनीतिक दलों की निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी देने का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। युवा केवल रैलियों में दिखाई देने वाली भीड़ नहीं हैं। वे नीति निर्माण, संगठन और लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया के सक्रिय भागीदार बनना चाहते हैं।

नई पीढ़ी की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि युवा अब केवल यह नहीं पूछना चाहता कि उसके लिए क्या किया जाएगा। वह यह भी पूछ रहा है कि अपने भविष्य के फैसलों में उसकी अपनी भूमिका क्या होगी। राहुल गांधी की युवा-केंद्रित राजनीति की वास्तविक परीक्षा भी इसी बिंदु पर होगी। रोजगार, शिक्षा, परीक्षा, तकनीक और



“कठिन परिस्थितियाँ कायरों को तोड़ती हैं और वीरों को निहारती हैं।” — सरदार वल्लभभाई पटेल

“अन्याय सहना उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि अन्याय करना।” — डॉ. राजेंद्र प्रसाद

आज का राशिफल



शुभ संवत् 2083, शके 1948, माह: आश्विन माह महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह (लगभग 5:52 AM) तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। दोपहर 11:46 AM से 12:33 PM तक (इस दौरान कोई भी नया वा धूम कार्य शुरू किया जा सकता है) बृह मुहूर्त (सुबह): प्रातः 04:38 AM से 05:26 AM तक।

आज जन्म लिए बालक का फल...

पश्चात्त्य ज्योतिष के अनुसार इस दिन पूर्व कन्या राशि में गेसर कर रहा होगा, जबकि जन्मतिथि के आधार पर बच्चे की सन साइन कर्लाणी, इनका व्यक्तित्व आकर्षक और शिष्टाचार उकृष्ट होता है। विद्वान् रम्याव के भी हो सकते हैं, जो लोक से हटकर सोचना पसंद करते हैं।

मेष राशि : घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें और उनका मान-सम्मान व आदर करें।

वृष राशि : आज आपको कोई नयी जानकारी मिलेगी आपके लिए यह जानकारी भविष्य में फायदेमंद साबित होगी।

मिथुन राशि : धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताइए।

गर्कट राशि : दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अपनी मेहनत और क्षमता पर विस्थास रखें।

सिंह राशि : समस्याओं से धराने के बजाय उनको सुलझाने की कोशिश करें।

कन्या राशि : पुंजी के उचित निवेश के लिए आपको किसी अनुभवी से सलाह लेनी चाहिए।

तुला राशि : काम करने के तरीकों में बदलाव करेंगे और व्यवस्थित रहेंगे तो इससे आपके काम जल्दी निपटेंगे।

वृश्चिक राशि : बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं पर एक बार फिर से विचार करें।

धनु राशि : भावनात्मक रूप से आप अपने आपको बहिया महसूस करेंगे।

मकर राशि : व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाने की भी जरूरत है। व्यवसाय में सुधार आएगा।

कुंभ राशि : ऑफिस में कुछ राजनीति जैसा माहौल रह सकता है।

मीन राशि : पैसों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे।

भारतीय समाज में जनजाति: वर्ण व्यवस्था के परे जमींदारी और सर्वर्ण पहचान !



श्वेताशु रंजन

भारतीय समाज में पहचान अक्सर एक ही खान में बाँध दी जाती है—या तो जनजाति, या सर्वर्ण। इतिहास और प्रशासनिक अनुभव दोनों बताते हैं कि यह द्विभाजन हमेशा सत्य नहीं रहा। जनस्थान का मौना समाज इसका जीवंत उदाहरण है। संविधान में अनुसूचित जनजाति होने के बावजूद मौना समाज ने अपनी क्षतिग्र-राजसी स्मृति, भूमि से जुड़ाव और सामाजिक सम्मान को पूरी तरह नहीं त्यागा। अनुसूचित जनजाति का दर्जा किसी समुदाय को स्वतः 'निम्न' नहीं बना देता; यह एक संवैधानिक श्रेणी है, जबकि सामाजिक स्मृति और संस्कृतिक आत्मबोध अलग स्तर पर चलते हैं। इसी भ्रष्टभूमि में भूमिहार समाज की पहचान को भी केवल मजाक या राजनीतिक नारे के रूप में नहीं, बल्कि विवेचना के विषय के रूप में देखा जाना चाहिए। कुछ शोधों में यह तर्क रखा गया है जिसमें लेखक का शोध निबंध भी है कि भूमिहार समुदाय लोकुर समिति के माण्डवेंडो- विशिष्ट संस्कृति, ऐतिहासिक अलगाव के संकेत, सामाजिक - आर्थिक संक्रमण और पारंपरिक जीवनशैली- के आलोक में विश्लेषण का हकदार है। निष्कर्ष से पहले निष्पक्ष आकलन जरूरी है। भूमिहार शब्द का आधिकारिक उल्लेख 1865 के आसपास संयुक्त प्रांतों के अधिलेखों में मिलता है। उसी वर्ष भारतीय वन अधिनियम भी आया, जिसके बाद घने जंगलों पर राजकीय नियंत्रण बढ़ा जो कि विशेषकर माधव और पूर्वाञ्चल के इलाकों में थे। भूमि, वन और सामुदायिक अधिकारों के इस ऐतिहासिक मोड़ को मात्र संयोग कहकर टाला नहीं जा सकता; इसे सामाजिक-आर्थिक इतिहास के साथ जोड़कर पढ़ना होगा। यह धारणा भी भ्रामक है कि पुजारी या ब्राह्मण वंश होने पर जनजातीय पहचान संभव नहीं। हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के गद्दी समुदाय में गद्दी ब्राह्मण पहाड़ी इलाकों में पशुपाल और पुरोहित दोनों से जुड़े रहे हैं, और उर्ध्व अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत भी रखा गया है। उत्तराखंड के जौनसार-बावर में

जौनसारी पहचान क्षेत्रीय-जनजातीय है। इस समूह में शर्मा, जोशी, नीटियाल जैसे स्थानीय ब्राह्मण परिवार भी शामिल हैं। भौगोलिक अलगाव ने यहाँ वर्ण और जनजाति को एक ही सामाजिक ढाँचे में साथ रखा। भूमि का प्रश्न और उलझा हुआ है। कृषि जंगणपन के अनुसार देश की कुल संचालित कृषि भूमि का लगभग ग्यारह प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजातियों के पास है। अंग्रेजी काल में मैदानी क्षेत्रों में व्यक्तिगत जमींदारी अधिक मजबूत हुई, जबकि अनेक जनजातीय-पहाड़ी इलाकों में भूमि सामुदायिक, रिहासती या पारंपरिक स्वामित्व पर टिकी रही। जमींदार होना अपने आप में जनजातीय स्मृति का अंत नहीं है। समाजशास्त्री जी.एस. थुर्न ने कुछ जनजातीय समूहों को उच्च सामाजिक स्तर वाले भूमिस्वामी और अभिजात वर्ग के रूप में भी देखा था। छत्तीसगढ़ के सोनाखान के वीर नारायण सिंह इसका ऐतिहासिक उदाहरण हैं। 1795 में जमींदार परिवार में जन्मे सिंह ने पैंतीस वर्ष की आयु में पिता रामराय से जमींदारी संपाली। वे बिंझवार आदिवासी समुदाय से जुड़े माने जाते हैं। कुछ पुराने पुस्तकों में उन्हें राजपूत बताया गया, जिसे बाद में सरकारी-ऐतिहासिक स्पष्टीकरणों में आदिवासी पृष्ठभूमि के साथ जोड़ा गया। 1857 के संघर्ष में वे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं। जमींदारी और जननायकत्व यहाँ एक-दूसरे के विरोधी नहीं थे।

भूमिहार समाज के सामने प्रश्न यह नहीं कि वह अपनी सर्वर्ण या ब्राह्मण दावेदारी छोड़े, बल्कि यह है कि क्या जनजातीय और उच्चवर्गीय पहचान साथ चल सकती है। मौना समाज ने दोनों को अपने ढंग से साभा। अगली पीढ़ी के लिए इतिहास, भूमि और संवैधानिक श्रेणियों का संयमित पुनर्पाठ जरूरी है—शरेबाजी नहीं, तथ्यों की परीक्षा। पहचान वर्ण व्यवस्था के परे भी बनती है; उसे होने पर जनजातीय पहचान संभव नहीं। हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के गद्दी समुदाय में गद्दी ब्राह्मण पहाड़ी इलाकों में पशुपाल और पुरोहित दोनों से जुड़े रहे हैं, और उर्ध्व अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत भी रखा गया है। उत्तराखंड के जौनसार-बावर में

चुनाव आयोग, एसआईआर और फॉर्म6: सवाल अब सुप्रीम कोर्ट तक

निमिषा सिंह
(दांव पर पारदर्शिता और मतदाता का भरोसा)
चुनाव सिर्फ मतदान के दिन की कुछ घंटों की प्रक्रिया नहीं है। उसके पीछे महीनों चलने वाली एक पूरी व्यवस्था होती है—मतदाता सूची तैयार करने से लेकर नाम जोड़ने और हटाने तक, दावों-आपत्तियों से लेकर अंतिम सूची जारी होने तक। इस पूरी प्रक्रिया में एक आम मतदाता स्वयं ज्यादा जिस चीज पर भरोसा करता है, वह है चुनाव आयोग। लेकिन जब उसी आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगें, उसके फैसलों को लेकर राजनीतिक दल आमने-सामने हों और आयोग के भीतर की कार्यप्रणाली भी सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनने लगे, तब मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रह जाता। फिर सवाल भरोसे का होता है। अभी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर यही हो रहा है। विपक्ष चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठा रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं। भाजपा और केंद्र सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे हैं और चुनाव आयोग के बचाव में भी सामने आ रहे हैं। यहाँ से एक अहम सवाल पैदा होता है—जब सवाल चुनाव आयोग से हैं, तो उसके बचाव की राजनीतिक दलों को उच्च सामाजिक स्तर वाले भूमिस्वामी और अभिजात वर्ग के रूप में भी देखा था। छत्तीसगढ़ के सोनाखान के वीर नारायण सिंह इसका ऐतिहासिक उदाहरण हैं। 1795 में जमींदार परिवार में जन्मे सिंह ने पैंतीस वर्ष की आयु में पिता रामराय से जमींदारी संपाली। वे बिंझवार आदिवासी समुदाय से जुड़े माने जाते हैं। कुछ पुराने पुस्तकों में उन्हें राजपूत बताया गया, जिसे बाद में सरकारी-ऐतिहासिक स्पष्टीकरणों में आदिवासी पृष्ठभूमि के साथ जोड़ा गया। 1857 के संघर्ष में वे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं। जमींदारी और जननायकत्व यहाँ एक-दूसरे के विरोधी नहीं थे।

भूमिहार समाज के सामने प्रश्न यह नहीं कि वह अपनी सर्वर्ण या ब्राह्मण दावेदारी छोड़े, बल्कि यह है कि क्या जनजातीय और उच्चवर्गीय पहचान साथ चल सकती है। मौना समाज ने दोनों को अपने ढंग से साभा। अगली पीढ़ी के लिए इतिहास, भूमि और संवैधानिक श्रेणियों का संयमित पुनर्पाठ जरूरी है—शरेबाजी नहीं, तथ्यों की परीक्षा। पहचान वर्ण व्यवस्था के परे भी बनती है; उसे होने पर जनजातीय पहचान संभव नहीं। हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के गद्दी समुदाय में गद्दी ब्राह्मण पहाड़ी इलाकों में पशुपाल और पुरोहित दोनों से जुड़े रहे हैं, और उर्ध्व अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत भी रखा गया है। उत्तराखंड के जौनसार-बावर में

तथ्य और दस्तावेज के साथ जवाब दे और सरकार यह सुनिश्चित करे कि पूरी प्रक्रिया इतनी पारदर्शी हो कि किसी को उसकी निष्पक्षता पर संदेह करने का मौका ही न मिले? क्योंकि चुनाव आयोग किसी सरकार का विभाग नहीं है। वह एक संवैधानिक संस्था है। उसकी विश्वसनीयता सत्ता के समर्थन से नहीं, उसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शी कार्यप्रणाली से बनती है। इसलिए इस पूरे विवाद को केवल भाजपा बनाम विपक्ष के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। एसआईआर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ मतदाता सूची के पुनरीक्षण तक सीमित नहीं रहा। इसके साथ चुनाव आयोग के फैसले उसी की प्रक्रिया, आयोग के भीतर मतभेद और कुछ प्रशासनिक फैसले भी चर्चा में आ गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव आयोग दूसरी तरफ कहता रहा है कि मतदाता सूची को अद्यतन रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है और पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक प्रक्रियाएँ मौजूद हैं। इन दोनों दावों के बीच असली सवाल यह है कि प्रक्रिया जमीन पर कितनी पारदर्शी और नागरिक के लिए कितनी सुरक्षित है। किसी मतदाता का नाम सूची से हटाना कोई सामान्य प्रशासनिक घटना नहीं है। उसके पीछे मतदान का अधिकार जुड़ा है। इसलिए नाम हटाने का कारण स्पष्ट

होना चाहिए, संबंधित व्यक्ति को जानकारी मिलनी चाहिए और आपत्ति तथा अपील का प्रयोग अवसर होना चाहिए। इस विवाद को और गंभीर बनाने वाली बात चुनाव आयोग के भीतर कथित असहमतियों की खबरें थी, वहाँ आयोग ने फार्म 6 के साथ इस अतिरिक्त घोषणा की आवश्यकता समाप्त कर दी। अब सवाल यह होना चाहिए कि शुरुआत में यह व्यवस्था क्यों लाई गई थी? उसका प्रशासनिक आधार क्या था? क्या उससे मतदाता पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था? और अगर बाद में उसे हटाने की जरूरत महसूस हुई, तो उसका कारण क्या था? इन सवालों का स्पष्ट जवाब देना चुनाव आयोग के हित में भी है। यहाँ से केंद्र सरकार और भाजपा की भूमिका भी चर्चा में आती है। जब विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है, भाजपा को तर्फ से कहा जाता है कि विपक्ष संवैधानिक संस्था की छवि खराब कर रहा है। लेकिन लोकतंत्र में यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि सरकार को प्रार्थमिकता क्या होनी चाहिए। क्या सरकार को चुनाव आयोग का राजनीतिक बचाव करना चाहिए या यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयोग अपने हर निर्णय का जवाब दस्तावेजों और नियमों के आधार पर दे? अगर विपक्ष का आरोप गलत है तो चुनाव आयोग के पास उसे तथ्यों के साथ खारिज करने के पर्याप्त साधन होने चाहिए। सरकार को हर सवाल का राजनीतिक जवाब देने की जरूरत

नहीं होनी चाहिए। और अगर प्रक्रिया में कहीं कमी है तो उसे स्वीकार करना भी संस्था की कमजोरी नहीं है। इसलिए सरकार से सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि वह चुनाव आयोग के पक्ष में क्यों बोल रही है। सवाल यह भी होना चाहिए कि वह आयोग के अधिक पारदर्शी बनाने के लिए क्या कर रही है। अब यह विवाद न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा भी बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के कामकाज और SIAR से जुड़े सवालों में जब अब मामलों की सुनवाई होगी तो चुनाव आयोग को अपने फैसलों और प्रक्रियाओं का कानूनी आधार स्पष्ट करना होगा। यदि केंद्र सरकार अदालत में चुनाव आयोग के फैसलों का बचाव करती है, तो यह उसका कानूनी अधिकार है। लेकिन इससे सवाल भी उठ सकता है कि सरकार और चुनाव आयोग एक ही तरफ क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसका सबसे बेहतर जवाब राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि पारदर्शिता और रिकॉर्ड हो सकते हैं। इस पूरे विवाद को भाजपा बनाम कांग्रेस, सरकार बनाम विपक्ष या मोदी सरकार बनाम चुनाव आयोग के रूप में देखना आसान है। लेकिन असली केंद्र में है मतदाता। वह नागरिक जिसे यह जानना है कि मतदाता सूची में उसका नाम है या नहीं, अगर कोई गलती हुई तो वह उसे ठीक करा सकता है या नहीं और मतदान के दिन उसकी आवाज व्यवस्था में दर्ज होगी

या नहीं। इसलिए आज सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा आयोजी रही। सवाल यह है कि चुनाव आयोग अपने ऊपर उठे सवालों का कितना स्पष्ट जवाब देता है। सरकार से भी सवाल यही है—क्या वह आयोग की राजनीतिक ढाल बनेगी, या ऐसी पारदर्शिता की मांग करेगी जिससे आयोग को किसी राजनीतिक ढाल की जरूरत ही न पड़े? विपक्ष से भी सवाल है—अगर आरोप गंभीर हैं तो क्या उनके साथ पर्याप्त दस्तावेज और प्रमाण सामने रखे जायेंगे? और मीडिया से भी सवाल है—क्या वह दोनों पक्षों के दावों के बीच जाकर सच की पड़ताल करेगा? चुनाव आयोग के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती किसी राजनीतिक दल को संतुष्ट करना नहीं है। उसे उस नागरिक को आश्वासन देना है जो अपना वोट डालते समय किसी पार्टी पर नहीं, व्यवस्था पर भरोसा करता है।

सरकारें बदलती हैं। सत्ता के समीकरण बदलते हैं। राजनीतिक आरोप भी बदलते रहते हैं। लेकिन चुनाव की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा कमजोर पड़ जाए, तो उसकी कीमत लंबे समय तक चुकानी पड़ सकती है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है—शोर कम हो और रिकॉर्ड सामने आएं। आरोपों से ज्यादा उनके बयान सुनने हैं।

(यह लेखिका के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

दवाओं और इलाज में लूट-खुलेआम कत्लेआम

रमन त्रेन
स्वास्थ्य सेवा किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी मानवीय जिम्मेदारी है। बीमार व्यक्ति डॉक्टर और अस्पताल के पास केवल इलाज के लिए नहीं जाता, वह अपना जीवन और भरोसा दोनों सौंपता है। इसलिए जब इसी भरोसे को मुनाफे का माध्यम बना दिया जाए तो सवाल केवल महंगे इलाज का नहीं, बल्कि समाज की संवेदनशीलता के संकट का बन जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कैसर की एक दवा का उदाहरण सामने आया, जिसकी कीमत रिटेलर के लिए लगभग 2,700 रुपये थी, लेकिन उसकी एमआरपी 27,000 रुपये तक बढ़ी। यानी कीमत में करीब दस गुना अंतर। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस पर बेहद गंभीर चिंता जताते हुए इसे मरीजों के साथ दिनदहाड़े लूट और 'कत्लेआम'

की कीमत बढ़ाते हैं। जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने से मरीज को रहस्य नहीं मिलेगा। सरकार की पहली जिम्मेदारी स्पष्ट और प्रभावी मूल्य नियंत्रण, पारदर्शी बिलिंग और नियमित निगरानी सुनिश्चित करना है।डीपीसी ओ -2013 और एन पीपी जैसी व्यवस्थाएँ मौजूद हैं। अदालत में सामने आए ऐसे मामलों से यह प्रश्न उठता है कि नियमन का लाभ वास्तव में मरीज तक पहुंच रहा है या नहीं। निजी अस्पतालों की भी यह समझना होगा कि अस्पताल उद्योग हो सकता है, लेकिन मरीज कोई 'ग्राहक' मात्र नहीं है। डॉक्टर के सामने बैठा व्यक्ति अपने जीवन के सबसे कमजोर क्षण में होता है। उसे भय दिखाकर अनावश्यक जांच, महंगी दवा, अतिरिक्त प्रक्रिया या अनावश्यक ऑपरेशन की ओर धकेलना चिकित्सा-व्यवस्था के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है। हालाँकि वह भी उतना ही जरूरी है कि ईमानदारी से सेवा करने वाले लाखों डॉक्टरों

और स्वास्थ्यकर्मियों को कुछ संस्थानों की गलत प्रथाओं के कारण सामूहिक रूप से दण्डी न ठहराया जाए। सबसे चिंताजनक स्थिति तब होती है जब सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का खर्च भी अंततः करदाता की जेब से जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी संदर्भ में सवाल उठाया कि यदि मरीज सरकारी योजना के अंतर्गत उपचार करा रहा है तो महंगी दवाओं की प्रतिपूर्ति का बोझ आखिर किस पर पड़ेगा—सरकार पर और अंततः जनता पर। मृत्यु के बाद भी अस्पताल का पूरा भुगतान न होने तक शव परिवर्तनों को न सौंपने जैसी शिकायतें इस व्यवस्था के मानवीय पक्ष पर और बड़ा प्रश्न खड़ा करती हैं। चिकित्सा सेवा में पैसा आवश्यक हो सकता है, लेकिन मनुष्यता उससे बड़ी है। भारत की परंपरा में चिकित्सा की सेवा माना गया। मंदिरों, धर्माश्रम संस्थाओं और समाजसेवियों ने औषधालय चलाए, गरीबों को मुफ्त दवा दी। आज

चिकित्सा विज्ञान ने असाधारण प्रगति की है, लेकिन यदि इलाज इतना महंगा हो जाए कि बीमारी से बचने के बाद परिवार आर्थिक रूप से समाप्त हो जाए, तो विकास दिशा पर पुनर्विचार जरूरी है। अब सरकार को केवल घोषणाएँ नहीं, बल्कि दवा की कीमत से लेकर अस्पताल के पैकेज, डॉक्टर की फीस, जांच, इम्प्लान्ट, फार्मसी और अंतिम बिल तक पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता लानी होगी। हर मरीज को दूसरी दुकान से दवा खरीदने की स्वतंत्रता, दवा की खरीद कीमत और मरीज से वसूली गई कीमत की स्पष्ट जानकारी तथा अनावश्यक उपचार के विरुद्ध स्वतंत्र शिकायत तंत्र मिलना चाहिए। न्यायपालिका का हस्तक्षेप स्वास्थ्ययंग्य है, लेकिन सवाल यह भी है कि अदालतों की टिप्पणियाँ और इलाज जमीन पर कितनी तेजी से लागू होते हैं। सरकार और नियामक संस्थाएँ यदि समय पर कार्रवाई करें तो हर मामले को

न्यायालय तक पहुंचाने की जरूरत ही क्यों पड़े? स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार का अर्थ केवल नए अस्पताल और अत्याधुनिक मशीनें नहीं हैं। असली विकास बन होगा जब गरीब और मध्यमवर्गीय व्यक्ति बीमारी को आर्थिक विनाश का पर्याय न समझें। आज जरूरत है कि सरकार, न्यायपालिका, डॉक्टर, अस्पताल, फार्मा उद्योग और समाज—सभी अपनी भूमिका को फिर से समझें। किसी युद्ध में बम और गोलियाँ मनुष्य को मारती हैं, लेकिन यदि स्वास्थ्य व्यवस्था में लालच हावी हो जाए तो बीमारी के बीच आर्थिक और मानसिक शोषण भी मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। इसलिए दवाओं और इलाज की लूट को केवल बाजार का विषय नहीं, मानव जीवन और सामाजिक न्याय का प्रश्न मानकर रोकना होगा। करना वह दिन दूर नहीं जब बीमारी से ज्यादा महंगे इलाज से लाखों लोगों की मौत हो जाएगी।

संक्षिप्त

समाचार

56 परिषदीय विद्यालयों में दूर हुई

शिक्षकों की कमी, 63 का समायोजन

वाराणसी, एजेंसी। बेसिक शिक्षा विभाग के 4 शुन्य और 52 एकल शिक्षकों वाले विद्यालयों के 63 शिक्षकों का समायोजन बुरुहपतिवार को कर दिया गया। सरलस शिक्षकों के समायोजन से जुड़ी प्रक्रियाएं सारनाथ के डायर परिसर में पूरी की गई। गांव से शहर के विद्यालयों में समायोजन के बाद कोई भी शुन्य शिक्षक वाला नहीं बचा। एकल और कम संख्या वाले विद्यालयों में भी शिक्षकों की कमी पूरी कर दी गई। बीएसए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश और बेसिक शिक्षा विभाग के संविध के निर्देश पर प्रक्रिया पूरी करई गई। शिक्षकों की ओर से चुने गए विकल्प के अनुसार और परिष्ठता के आधार पर तैनाती की गई। समायोजन के बाद बाद नगर के 56 विद्यालयों में 4 शुन्य शिक्षकों वाले विद्यालय, 52 एकल और छत्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में तैनाती दी गई।

हेल्पलाइन पर संपर्क कर घर

से हटाए ई-वेस्ट

वाराणसी, एजेंसी। घर से निकलने वाले ई-वेस्ट का समुचित निदान किया जाएगा। नागरिकों को सबसे पहले लेबलिंग नंबर 8335955000 से संपर्क करना होगा। इसके बाद पिकअप के लिए सुविधाजनक समय और तिथि निर्धारित की जाएगी। तय समय पर टीम पहुंचकर ई-वेस्ट एकत्र करेगी। उसका उचित मूल्य देगी। पर्यावरण के जनकार आर्केड सिंह ने बताया कि ई-वेस्ट को लैंडफिल में डालने या खुले में फेंकने से सीसा, पारा, कैडमियम और निकल जैसे विषैले तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है। बाहिर के पानी के साथ ये हानिकारक रसायन भोजन, नदियों, झीलें और अन्य जल स्रोतों में मिल जाते हैं, जिससे पौते का पानी दूषित होता है। ई-वेस्ट को जलाने पर तेलोरेपलोलोकार्बन, बैरियम और अन्य विषैले रसायन हवा में फैल जाते हैं। इससे ओजोन परत को क्षति पहुंचती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। नगर निगम के अनुसार, एकत्र किए गए ई-वेस्ट को अधिकृत प्चैनलों से सुरक्षित पैनालइजेथन और वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। नगर आरकट हिमांशु नागपाल ने कारीवासियों से अपील की है कि वे पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को कल की समस्या न बनने दें। ई-वेस्ट को गीले या सूखे सामान्य कचरे के साथ न मिलाकर अलग रखें और अधिकृत संस्था को ही दें।

स्वाइन फ्लू की चपेट में मिलीं

दो बुजुर्ग महिलाएं

बरेली, एजेंसी। जिले में स्वाइन फ्लू मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को दो बुजुर्ग महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद संख्या 36 पहुंच गई है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. प्रशांत रंजन के मुताबिक, शैड रिपोर्टिंग टीम मरीजों के घर पहुंचेगी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, बहेड़ी की 83 वर्षीय और जखीरा की 75 वर्षीय महिलाओं की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों मरीजों की निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों के संपर्कों में आए लोगों की जानकारी गुप्ताने के साथ उनकी जांच आदि की प्रक्रिया कर रही है। इससे पहले 28 सितंबर को सुभाषनगर के 74 वर्षीय बुजुर्ग पॉजिटिव मिले थे। सर्विलांस अधिकारी ने बुझार, खासी, सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण पर चिकित्सकीय सलाह लेने की आह्वान की है।

सड़क बनाने में देरी, बंदरों का

आतंक और हाईटेशन लाइन

के मुद्दे नहीं सुलझे

बरेली, एजेंसी। बिहारतगन में इफको मार्ग से नैनपुर गांव लेकर हल्द्वगला तक सड़क बनाने में से रही देरी, खुद पशुओं व बंदरों का आतंक, हाईटेशन लाइन समेत कई मुद्दे शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में भी नहीं सुलझ सके। शनिवार को बहेड़ी, आंवला, नवाबगंज, फरीदपुर और मीरगंज तहसील परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में मौजूद अधिकारियों ने इन मुद्दों को सुलझाने का आश्वासन दिया। हालांकि सभी तहसीलों में जनसुनवाई के दौरान 337 शिकायतों में से 38 का ही निस्तारण करया गया। शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए गए।मीरगंज तहसील समगार में शनिवार को किसी कारणावश सीडीओ नहीं पहुंच सकी। हालांकि एसडीएम निधि शुक्ला और सीओ अजय कुमार ने 38 शिकायतें सुनीं, जिनमें दो शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। ग्राम पंचरूप उर्फ लमकन निवासी मोहनमंद हसन ने गांव की गलियों में फैली गंदगी और कीचड़ की समस्या उठाई। कुल्ला खुद निवासी मोहन स्वल्प ने गांव में बंदरों और खुद साइं के आतंक से निजात दिलाने की गुहार लगाई। सीडीओ के नहीं आने पर शिकायतकर्ता नासुदु दिसे बिहेड़ी में एसडीएम प्रसासन प्रीतिना सिंह ने 29 शिकायतों में से 9 का मौके पर निस्तारण करया। आदरं कॉलोनी, सिंह गौटिया, केशव पुरम, जानुनगर आदि मोहल्लों के लोगों ने शिकायत की कि नल्लेी रोड पर लोक निर्माण विभाग की ओर से केसर रेलवे क्रॉसिंग से सीसी रोड चौड़ीकरण और नाला निर्माण का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में ये काम तय समयसीमा परचवीं तक नहीं हो सकेगा। हालांकि एडीएम ने पीडब्ल्यूडी को कार्य में तेजी लाने की हिदायत दी। इसके अलावा लोगों ने केसर रेलवे क्रॉसिंग पर अवैध ई-रिहाश बंदे, जाम, अतिक्रमण व कार्यबंद न होने, गन्ना भुगतान का मुद्दा उठवा।तहसील फरीदपुर में अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिया। आज्ञा ने 63 शिकायतों में से सात का निस्तारण करया, जबकि शेष शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए।

प्रदेश के हर जिले से पूरी तरह से विदा हुआ मानसून

धूप बढ़ने से दिन और रात के तापमान में दस डिग्री का अंतर

लखनऊ , एजेंसी। उत्तर प्रदेश से शनिवार को वर्षा ऋतु की विदाई हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और गुजरात से भी मानसून लौट गया है।

इसके साथ ही अब मौसम में शरद ऋतु का हल्का असर दिखने लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं और सहारनपुर में शनिवार सुबह हल्के कोहरे की चादर दिखी। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी सुबह-शाम हवा में ठंडक महसूस होने लगी है।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले दो दिन तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं हैं। पुरवा हवाओं के प्रभाव से बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। इसके चलते सोमवार और मंगलवार को तराई के जिलों में छिड़पुट बूंदबांदी होने की संभावना है। हालांकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः



साफ रहने की उम्मीद है।

दिन-रात के पारे में 10 डिग्री का अंतर : यूपी से मानसून की विदाई के साथ राजधानी के मौसम में बदलाव महसूस होने लगा है। सुबह और शाम की हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी है। हालांकि, दिन में तेज धूप अब भी गर्मी का अहसास करा रही है। शनिवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री दिन और रात के तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार से पुरवा हवाओं के असर से बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। हालांकि, बारिश की संभावना नहीं है। बादलों की मौजूदगी से तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। शनिवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा, जो शुक्रवार के मुकाबले स्थिर रहा। न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कृष्णांजलि नाट्यशाला असुरक्षित.. दो मंचों पर ही सजेगी सांस्कृतिक शाम

अलीगढ़, एजेंसी। करीब चार दशक से नुमाइश की सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रही कृष्णांजलि नाट्यशाला इस बार कार्यक्रमों की मेजबानी नहीं कर सकेगी। आईआईटी बीएचयू ने अपनी जांच रिपोर्ट में इसे गतिविधियों के लिए असुरक्षित बताया है। ऐसे में इस बार नुमाइश के सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम केवल कोहिनूर और मुकाकाश मंच पर ही आयोजित होंगे।

1984-85 में जिला पंचायत के सहयोग से कृष्णांजलि नाट्यशाला का निर्माण हुआ था। उस समय जिलाधिकारी ललित श्रीवास्तव और एडीएम सिटी बाबा हरदेव सिंह थे।



कृष्णांजलि में वर्षों तक नाटक, संगीत, नृत्य, कवि सम्मेलन और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे। मंच पर कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ दर्शक दीर्घा में बैठी भीड़ नुमाइश की शामों का अहम हिस्सा रही।

2017 में कृष्णांजलि को आधुनिक ऑडिटोरियम में बदलने का प्रस्ताव सामने आया। इसके बाद वर्ष 2020 में नुमाइश समिति ने पुराने भवन को जर्जर घोषित करते हुए उसे गिराकर नया ऑडिटोरियम बनाने का

प्रस्ताव रखा था। इसके लिए करीब तीन करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किए जाने की बात सामने आई थी।

ऑडिटोरियम की है योजना : कृष्णांजलि नाट्यशाला की जगह बड़ा ऑडिटोरियम बनाया जा सकता है। यह आधुनिक और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर होगा। इसकी योजना धरातल पर उतरने में समय लगेगा। - आईआईटी बीएचयू की रिपोर्ट के अनुसार, कृष्णांजलि नाट्यशाला की संरचना मानव गतिविधियों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार नुमाइश में यहां कोई भी कार्यक्रम नहीं कराने का फैसला लिया गया है।

अजय राय की कुर्सी जाने के पीछे की वजह आई सामने

रिपोर्ट बनी आधार; सपा को भी संदेश देने की कोशिश

लखनऊ, एजेंसी। प्रदेश

प्रभारी से महीनों चली खींचतान की कीमत उतर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी कुर्सी गंवाकर चुकानी पड़ी, और इसी बहाने पार्टी ने अपने पुराने सामाजिक समीकरण की ओर लौटने का बड़ा दांव भी चल दिया। विधानसभा चुनाव से करीब पांच महीने पहले कांग्रेस आलाकमान ने अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर रामपुर खास से विधायक आराधना मिश्रा मोना को कमान सौंप दी है।

प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से टकराव में हुई राय की इस विदाई के साथ ही सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष और देवेन्द्र निषाद व आलोक प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूरब से ब्राह्मण और महिला चेहरा मोना, पश्चिम से मुस्लिम चेहरा मसूद, दलित प्रभारी गौतम और उपाध्यक्षों के जरिए पिछड़ों को जगह देकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सपा से सीट बंटवारे की बातचीत और 2027 की लड़ाई वह अस्सी और नब्बे के दशक वाले ब्राह्मण-दलित-मुस्लिम-पिछड़ा समीकरण के सहारे लड़ना चाहती है। नई टीम तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राय और गौतम के बीच इस कदर ठन गई थी कि गौतम ने आलाकमान को साफ शब्दों में प्रदेश नेतृत्व बदलने की रिपोर्ट सौंप दी थी। गौतम किसी भी कीमत पर राय के साथ चलने



को तैयार नहीं थे। आंबेडकरवादी राजनीति से आने वाले गौतम ने राय के मंदिर जाने पर सवाल उठाए थे और उनका तर्क था कि राय की शैली से दलित मतदाता कांग्रेस से नहीं जुड़ेंगे। गौतम खेमे की शिकायत यह भी थी कि राय संगठन में किसी को तबज्जो नहीं देते।

टकराव सतह पर भी दिखने लगा था। 23 सितंबर को नाराज कार्यकर्ताओं की बैठक में गौतम अकेले नजर आए, राय वहां नहीं पहुंचे। मायावती से मुलाकात की कोशिश, जिलाध्यक्षों में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व और सपा से सीट बंटवारे जैसे मुद्दों पर भी दोनों की राह अलग थी।यह लड़ाई दिल्ली दरबार तक फैली थी। राय को संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल का करीबी माना जाता है, जबकि गौतम राहुल गांधी के भरोसेमंद हैं। अटकलों के बीच राय ने पिछले दिनों खरों से लेकर राहुल गांधी तक से मुलाकात की और यह दावा भी किया कि कोई बदलाव नहीं हो रहा। लेकिन आखिरी फैसला राहुल गांधी के हाथ में था और पलड़ा गौतम का थोरा रहा।

लेकर आने वाले समय में विस्तार से चर्चा होगी।

मौर्य ने कहा विपक्षी दलों का एक ही उद्देश्य है, भाजपा हटाओ देश बचाओ और संविधान बचाओ। आज देश में राहुल गांधी ही अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, जनजातियों और पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं। उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में यही काम कर रही है। इसलिए समान विचारधारा को लेकर ही वह गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और सैनी समाज के बड़े नेता हैं। उनका यूपी में करीब 8-9 फीसदी वोटबैंक है। इससे पहले 2022 में वह भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे, फिर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी।

छिपाएं नहीं, बच्चे में दूसरे जेंडर वाले

लक्षण दिखें तो तुरंत लें डॉक्टर की सलाह

लखनऊ, एजेंसी। लड़के के तौर पर जन्मे क्रिकेटर संजय बांगड़ के बेटे आर्यन ने हॉर्मोनल बदलाव के चलते पूरी तरह से लड़की बनना स्वीकार किया। घरवालों ने भी उनका साथ दिया और आज वह बिना शर्म और संकोच के लड़की के रूप में समाज के सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक डर के चलते लोग आज भी इसे छिपाते हैं। डॉक्टरों के अनुसार अगर आपका बच्चा विपरीत जेंडर जैसा व्यवहार करे तो छिपाने के बजाय उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं।

जेंडर परिवर्तन सर्जरी करने

वाले केजीएमयू में यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विश्वजीत सिंह के अनुसार जन्म के समय मां-बाप को बच्चे की जननांग संबंधी विकृति का पता तुरंत चल जाता है। सामाजिक लोक-लाज के फेर में वे इसे छिपाने में लगे रहते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि समय के साथ ही यह विकृति सभी को पता चल जाएगी। इसके बजाय अगर डॉक्टर का परामर्श लिया जाए तो संभव है कि काफी मामलों में बच्चे को पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री बनाया जा सके। हॉर्मोनल बदलावों के मामले में भी यह बात लागू होती है।

संतोष वाल्मीकि की पुस्तक रेडियो कल और आज के अंग्रेजी संस्करण रेडियो पास्ट एंड प्रेजेंट का विमोचन किया गया

किताबों के पन्नों से निकली रेडियो की कहानी, मीडिया के भरोसे पर हुई चर्चा

लखनऊ , एजेंसी। कभी शहर हो या गांव, अमीर हो या गरीब-रेडियो हर जगह लोगों की आवाज और मनोरंजन का साथी रहा है। शनिवार को बलरामपुर गार्डन में चल रहे राष्ट्रीय पुस्तक मेले में रेडियो के इसी सफर की कहानी किताब के पन्नों से मंच तक पहुंची। यहां संतोष वाल्मीकि की पुस्तक रेडियो कल और आज के अंग्रेजी संस्करण रेडियो पास्ट एंड प्रेजेंट का विमोचन किया गया। इस मौके पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रेडियो के व्यापक प्रभाव को रेखांकित पाया।

वंदे मातरम की थीम पर चल रहे पुस्तक मेले में एक स्टॉल पर कई नई किताबें भी पाठकों के बीच चर्चा में हैं। इनमें योगेंद्र यादव की गणराज्य का स्वप्नर्ष, कार्ल मार्क्स की संघर्षपूर्ण जीवन गाथा और क्रांति पर आधारित मैरी ग्रेबियल की हिंदी अनुवादित प्रेम और पूंजी शामिल हैं। ममता कालिया की संस्मरणात्मक पुस्तक शेषकथा और राजीव कुमार की

जहांआरा पादशाही बेगम भी नए प्रकाशनों में शामिल हैं।

गजलों से सजी शाम : पुस्तक मेले की शाम लखनऊ के प्रसिद्ध शायर रामप्रकाश बेखुद के नाम रही। उनके साथ कृपाशंकर विश्वास, सरलता जमाल, बद गोरखपुरी, रचना मिश्रा और नवीन शुक्ल ने गजलें पढ़ीं। गजलों की सुरमयी प्रस्तुतियों ने मेले के साहित्यिक माहौल को और रंग दिया।पुस्तक मेले में हर दिन युवाओं की भीड़ बढ़ रही है। एक स्टॉल के प्रभारी एमएफएम शर्मा ने बताया कि युवा सेक्टर हेल्प किताबें काफी पसंद कर रहे हैं। इनमें एटोमिक हैबिट्स, माइंडसेट, द पावर ऑफ नाओ और द साइकोलॉजी ऑफ मनी की मांग ज्यादा है। मोटिवेशनल किताबों में इकिगाई की मांग सबसे अधिक है।

तस्वीरों से सीख रहे बच्चे: एक अन्य स्टॉल पर बच्चों की उम्र के हिसाब से एक्टिविटी और कहानी की किताबें उपलब्ध हैं।



स्टॉल की प्रभारी गरिमा ने बताया कि इनमें सोशल इमोशनल लर्निंग, विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित किताबें शामिल हैं। बच्चों को सिर्फ लिखकर सिखाने के बजाय तस्वीरों के माध्यम से सीखने पर जोर दिया गया है, ताकि वे चीजों को लंबे समय तक याद रखें और किताबों से जुड़ाव महसूस करें।

एटोमिक हैबिट्स से साइकोलॉजी ऑफ मनी तक, मोटिवेशनल किताबों की बढ़ी मांग किताबों के मेले में इस बार युवाओं की पसंद सिर्फ कहानी और साहित्य तक सीमित

नहीं है। वे अपनी आदतों, सोच और जीवन को बेहतर बनाने के रास्ते भी किताबों के पन्नों में तलाश रहे हैं। बलरामपुर गार्डन में चल रहे राष्ट्रीय पुस्तक मेले में हर दिन युवाओं की भीड़ बढ़ रही है। एक स्टॉल के प्रभारी के मुताबिक, युवाओं में सेल्फ हेल्प किताबों की मांग काफी ज्यादा है। एटोमिक हैबिट्स, माइंडसेट, द पावर ऑफ नाओ और द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी किताबें पसंद की जा रही हैं। वहीं, मोटिवेशनल किताबों में इकिगाई की मांग सबसे ज्यादा है। मेले में बच्चों के लिए भी उम्र के

हिस्साब से एक्टिविटी और कहानी की किताबें उपलब्ध हैं। एक अन्य स्टॉल की प्रभारी गरिमा ने बताया कि इनमें सोशल इमोशनल लर्निंग, विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित किताबें शामिल हैं। बच्चों को सिर्फ लिखकर सिखाने के बजाय तस्वीरों के माध्यम से सीखने की कोशिश की गई है, ताकि वे चीजों को लंबे समय तक याद रखें और किताबों से जुड़ाव महसूस करें।

रेडियो के सफर से रूबरू हुए पाठक : मेले में साहित्य के साथ रेडियो और मीडिया की दुनिया भी चर्चा में रही। शनिवार को संतोष वाल्मीकि की पुस्तक रेडियो कल और आज के अंग्रेजी संस्करण रेडियो पास्ट एंड प्रेजेंट का विमोचन हुआ। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि रेडियो ऐसा माध्यम रहा है, जिसे अमीर-गरीब, शहर-गांव हर जगह सुना जाता रहा है। वंदे मातरम की थीम पर चल रहे मेले में एक स्टॉल पर योगेंद्र यादव की गणराज्य

का स्वधर्म, कार्ल मार्क्स की संघर्षपूर्ण जीवन गाथा और क्रांति पर आधारित मैरी ग्रेबियल की हिंदी अनुवादित प्रेम और पूंजी चर्चा में हैं। ममता कालिया की संस्मरणात्मक पुस्तक शेषकथा और राजीव कुमार की जहांआरा पादशाही बेगम भी नए प्रकाशनों में शामिल हैं। कार्यक्रम में मीडिया - सवाल भरोसे का विषय पर परिचर्चा हुई। इसमें एमएलसी तालजी प्रसाद निर्मल, असम से बैजनाथ बांसफोर, पूर्व उधमहान्दिदेशक दूरदर्शन डॉ. सतीश ग्रोवर, रेडियो आर्टिस्ट रज्जनलाल, दूरदर्शन कार्यक्रम प्रमुख आत्मप्रकाश मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार बृजेश शुक्ल, आलोक जोशी, रमा अरुण रेनू चतुर्वेदी और आरजे प्रतीक ने विचार व्यक्त किए।गजलों की शाम लखनऊ के प्रसिद्ध शायर रामप्रकाश बेखुद के नाम रही। उनके साथ कृपाशंकर विश्वास, सरलता जमाल, बद गोरखपुरी, रचना मिश्रा और नवीन शुक्ल ने गजलें पढ़ीं।



राहुल ने धोनी की बराबरी की, युवराज का रिकॉर्ड तोड़ा

न्यू चंडीगढ़। भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में दमदार बल्लेबाजी की। राहुल को इस सीरीज में पहली बार बल्लेबाजी का मौका मिला और उन्होंने जमकर गेंदबाजों की धुनाई की। राहुल ने नाबाद शतक लगाया जिससे भारत बड़ा लक्ष्य देने में सफल रहा। इसके साथ ही राहुल ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली है।

भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे मैच में 352 रनों का लक्ष्य दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और 50 ओवर में सात विकेट पर 351 रन बनाए। भारत के लिए केएल राहुल ने नाबाद शतक लगाया,

जबकि रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और टीम ने शुभमन गिल और विराट कोहली के विकेट जल्द गंवा दिए थे।

राहुल ने संभाला मोर्चा

शुरुआती झटकों के बाद रोहित शर्मा और ऋतुराज ने पारी को संभाला। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई। रोहित हालांकि, शतक पूरा नहीं कर सके और 92 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, ऋतुराज ने 57 रनों की पारी खेली। इसके बाद केएल राहुल ने मोर्चा संभाला ने शानदार शतक जड़ा। इस सीरीज में राहुल को पहली बार बल्लेबाजी का मौका मिला था और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। राहुल 87 गेंदों पर 10 चौकों और छह छक्कों की मदद से नाबाद 129 रन बनाए। वहीं, नमन धीरे ने 30, अंशुल कंबोज ने 17 और नीतीश रेड्डी ने 9 रन बनाए। गुरुर बरार 8 रन बनाकर नाबाद रहे। वेस्टइंडीज की ओर से जेडन

पांचवें स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए लगाया चौथा शतक

केएल राहुल ने भारत के लिए पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए वनडे शतकों की खास सूची में धोनी की बराबरी कर ली है। राहुल अब धोनी के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं, जिनके नाम इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए चार शतक हैं। मुल्लानपुर में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 87 गेंदों पर नाबाद 129 रनों की तूफानी पारी खेली। भारत के लिए पांचवें नंबर के बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने 99 मैचों में सात शतक जड़े हैं।



सील्स को तीन विकेट मिले, जबकि कीमो पॉल को दो और गुडकेश मोती को एक विकेट मिला। इसके अलावा राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में भारत के पांचवें नंबर के बल्लेबाज द्वारा सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। राहुल ने युवराज के 2005 में कोलंबो में बनाए गए 110 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़

दिया है। राहुल ने अपनी पारी के दौरान शुरुआत में मध्य ओवरों में क्रीज पर टिककर एंकर की भूमिका निभाई, स्ट्राइक को रोस्ट किया और विरोधी गेंदबाजों की गलतियों का फायदा उठाकर बाउंड्री बटोरें। पारी के अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने अंदाज में गियर बदला और भारत का स्कोर 350 के पार तक पहुंचा दिया।

संक्षिप्त

समाचार

जी -20 में भारत की दो टूक, डब्ल्यूटीओ के नियमों से ही चलेगा व्यापार

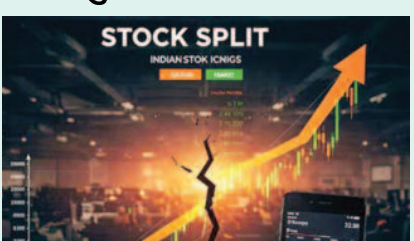
नई दिल्ली, एजेंसी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका में त-20 के वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रियों के सम्मेलन में यह आरोप खारिज किया कि भारत में कुछ सेक्टरों में जरूरत से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है, जिससे किसी दूसरे देश के उद्योगों के हितों को नुकसान पहुंच सकता हो। गोयल ने कहा कि भारत अपने आप में विशाल देश है और अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ यह वैश्विक स्तर पर आवश्यकताओं की पूर्ति में भी मदद करता है। उन्होंने कहा कि उत्पादन और सप्लाई चेन का दौरा बढ़ाना एक वाजिब मकसद है, लेकिन इसकी आड़ लेकर नियमों से बाहर के कदम नहीं उठाए जा सकते हैं और विकासशील देशों पर बोझ नहीं डाला जा सकता है। गोयल की यह बात इस मायने में अहम है कि अमेरिका की अगुवाई में त-20 में यह मुद्दा उठाया गया। साथ ही अलग से अमेरिका अपने सेक्शन 301 के तहत यह जांच कर रहा है कि भारत सहित 60 देशों में स्टील, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स सहित कुछ सेक्टरों में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता होने से अमेरिकी हितों को नुकसान हो रहा है या नहीं।



भारत की दलील
गोयल ने कहा, 'जी-20 प्रेसिडेंसी ने जिन सेक्टरों को चिन्हित किया है, उनमें भारत के पास स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी नहीं है।' पीयूष गोयल ने कहा कि कई देशों ने यह चिंता जताई है कि कुछ देशों में अपने हितों को बढ़ावा देने की हरकतों से डंपिंग और कम दाम पर माल दूसरे देशों में उतारने की स्थिति बन सकती है और भारत की भी ऐसी ही चिंता है। अमेरिका के टैरिफ दबाव और भारत समेत 60 देशों में 'ओवरकैपेसिटी' की जांच के बीच गोयल ने त-20 बैठक में भारत पर लगे आरोप को खारिज किया।

3 कंपनियों के शेयरों का होने जा रहा है बंटवारा, इसी हफ्ते हुआ ऐलान
नई दिल्ली, एजेंसी। तीन कंपनियों के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। इन कंपनियों ने इसी हफ्ते स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। आइए जानते हैं कि यह तीन कंपनियों कौन सी हैं। कितने टुकड़ों में इनके शेयरों को बांटा जाएगा।

इस कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। गुरुवार को मार्केट के बंद होने के समय पर इस स्टॉक की कीमत 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद 92.63 रुपये थी। कंपनी के शेयरों में लोअर सर्किट लगा था। बता दें, पिछले एक साल में शेयरों का दाम 43 प्रतिशत बढ़ चुका है।



कंपनी के शेयरों को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयरों का दाम घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए 30 अक्टूबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम 30 अक्टूबर को कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें ही स्टॉक स्प्लिट का लाभ मिलेगा। गुरुवार को इस कंपनी के शेयरों में भी लोअर सर्किट लगा था। 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में स्टॉक की कीमत 363.85 रुपये के स्तर पर आ गया था।

महंगाई बहुत बढ़ गई है 45 लाख में अफोर्डेबल हाउस नहीं बन सकता

कोलकाता, एजेंसी। सरकार ने सबको छत दिलवाने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की नीति बनाई है। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और जमीन एवं मकान बनाने वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि सात साल पहले बनी नीति अब बेमानी हो चुकी है। इसलिए देश के रियल एस्टेट डेवलपर्स चाहते हैं कि इस नीति में बदलाव हो। यही नहीं, सरकार अफोर्डेबल हाउस की परिभाषा में भी बदलाव करे। वे चाहते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग की कीमत में कोई कैपिंग नहीं हो। अभी इसमें 45 लाख रुपये की कैपिंग है।

क्रेडॉई ने की है मांग
भारत में 13,000 से भी अधिक रियल एस्टेट डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन इसका इन दिनों महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन कोलकाता में हो रहा है। इसी दौरान क्रेडॉई के प्रेसिडेंट शेखर पटेल ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सरकार अफोर्डेबल हाउस की परिभाषा बदले। उनका कहना है कि साल 2029 में जो तय हुआ था कि 45 लाख रुपये तक की कीमत के मकानों को ही अफोर्डेबल हाउस माना जाए, उसे हटाना होगा। क्योंकि जिस हिसाब से जमीन की कीमत बढ़ रही है और कंस्ट्रक्शन मैटेरियल महंगा हो रहा है, इतने में मकान बनाना संभव नहीं है।

सीआरडीआईआई ने सरकार से यह रखी मांग



मानदंड में सिर्फ आकार शामिल हो
पटेल का कहना है कि इस समय अफोर्डेबल हाउसिंग की नीति में मकान का आकार और मकान की कीमत, दोनों को मानक बनाया गया है। लेकिन अब सरकार को चाहिए कि वह मकान की कीमत की सीमा हटा दे। अफोर्डेबल हाउसिंग में सिर्फ निर्धारित आकार को ही मानदंड बनाया जाए। इस समय देश में सात मेट्रोपॉलिटन शहरों में 60 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाले मकान और अन्य इलाकों में 90 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाले मकानों को इस श्रेणी में रखा गया है। साथ ही उन मकानों की कीमत में 45 लाख रुपये की ऊपरी सीमा या कैपिंग भी तय की गई है। इससे अधिक कीमत के मकानों को

नोएल टाटा ने मांगा टाटा संस की मीटिंग का वीडियो, चंद्रशेखरन की नियुक्ति पर सवाल उठाए



नई दिल्ली, एजेंसी। टाटा ग्रुप में अब लेटर वॉर शुरू हो गया है। टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच ने हाल में एकदूसरे को कई पत्र लिखे हैं। ताजा घटनाक्रम में टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने टाटा संस बोर्ड को पत्र लिखकर 17 सितंबर की मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग और मिनट्स की जानकारी मांगी है। इस मीटिंग में एन चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन नियुक्त करने का फैसला लिया गया था।

नोएल टाटा ने 30 सितंबर को टाटा संस के बोर्ड को यह पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने उस तरीके पर भी सवाल उठाए जिससे बोर्ड ने मीटिंग के बाद चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को सही ठहराने के लिए दो कानूनी राय पेश कीं। नोएल टाटा का कहना था कि उन्हें मीटिंग में देश के पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ से मिली कानूनी राय के खास बिंदुओं को विस्तार से बताने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। नोएल टाटा ने दावा किया कि प्रस्ताव को नॉमिनेशन एंड रेमुनेरेशन कमिटी की जानकारी के तौर पर पास किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि नोएल टाटा चंद्रचूड़ की रिपोर्ट के आधार पर कास्टिंग वोट और टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे। उनका तर्क है कि उसके मूल कंटेंट और समय-समय पर किए गए बदलावों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

नोएल टाटा ने 17 सितंबर को टाटा संस बोर्ड के सामने चंद्रचूड़ की रिपोर्ट पेश की और तर्क दिया कि टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर्स को मिले खास वोटिंग अधिकारों को ओवरराइड करने के लिए टाटा संस के चेयरमैन के कास्टिंग वोट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

17 सितंबर को टाटा संस के बोर्ड ने चंद्रशेखरन को 4-1 के बहुमत से फिर से पांच साल के लिए चेयरमैन नियुक्त करने का फैसला किया था। केवल नोएल टाटा ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया था। बोर्ड में ट्रस्ट के दूसरे नॉमिनी वेणु श्रीनिवासन ने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का समर्थन किया। यह बैठक के उस फैसले के बाद हुई थी, जिसमें उसने टाटा संस की प्राइवेट और अनलिस्टेड बने रहने की अपील को ठुकरा दिया था।

किसी डायरेक्टर के पास बोर्ड मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग की पूरी कॉपी पाने का कोई असीमित अधिकार नहीं है। लेकिन स्क्रेटेरियल गाइडेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उपाय बताते हैं कि डायरेक्टर को कुछ खास रिकॉर्डिंग देखने की इजाजत दी जा सकती है ताकि वे चर्चा की पुष्टि कर सकें और फाइनल होने से पहले ड्राफ्ट मिनट्स पर कोई टिप्पणी (अगर हो तो) दे सकें।

आवश्यकता आविष्कार की जननी', डिमांड-सप्लाई का गैप पकड़ लगाया दांव, 3 साल में बनाई 3 करोड़ की कंपनी

नई दिल्ली, एजेंसी। यह कहानी है मोहिता गुप्ता इंद्रायण की। वह दिल्ली से हैं। उन्होंने डिमांड और सप्लाई के गैप को पहचानकर एक सफल फैशन ब्रांड खड़ा कर दिया है। इसका नाम 'सिंग सोल' है। साल 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। मोहिता ने इस गैप को तब महसूस किया जब उन्होंने देखा कि जहां एक ओर रेडिमेड कपड़ों में मनपसंद फिटिंग पाना मुश्किल होता है। वहीं दूसरी ओर लोकल बुटीक या डिजाइनर्स के पास जाने पर जेब ढीली करनी पड़ती है। यह ब्रांड पारंपरिक भारतीय कपड़ों और जीरो वेस्ट की मिसाल बनकर 3 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर के आंकड़े को पार कर चुका है। आइए, यहां मोहिता गुप्ता इंद्रायण की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं।

पहला बिजनेस करना पड़ा बंद

मोहिता दिल्ली में जन्मी और देश-विदेश के अलग-अलग हिस्सों में पली-बढ़ीं। कपड़ों और भारतीय विरासत से उनका पुराना नाता रहा है। लेडी श्री राम कॉलेज से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने दिल्ली से अपरेल मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग की पढ़ाई की। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर साल 2010 में बच्चों के कपड़ों का ब्रांड '612 लीग' शुरू किया। यह बड़ा किड्सवियर ब्रांड बनकर उभरा। हालांकि, कोरोना महामारी के दौरान फिजिकल स्टोर आधारित



यह बिजनेस बंद करना पड़ा। लेकिन, मोहिता के भीतर फैशन और भारतीय विरासत से जुड़ा कुछ नया करने की ललक कायम रही।

डिमांड-सप्लाई के इस गैप को पकड़ा

'612 लीग' के बाद मोहिता ने बाजार का गहराई से अध्ययन किया। पाया कि 5,000 से 15,000 रुपये के बीच के 'मास-प्रीमियम' सेगमेंट में बड़ा खालीपन है। ग्राहकों के पास या तो रेडी-टू-वियर के रूप में सीमित ऑप्शन थे या फिर अनिश्चित क्वालिटी वाले लोकल बुटीक। इस समस्या का समाधान निकालते हुए उन्होंने 2023 में गुरुग्राम से 'सिंग सोल' की शुरुआत की। इसका

मकसद महिलाओं को बिना डिजाइनर कीमतों के उनकी पसंद के कट, डिजाइन और साइज के अनुसार कस्टमाइज्ड और सुविधाजनक कपड़े उपलब्ध कराना था। बिजनेस के शुरुआती दिनों में गुरुग्राम के यूनिट में दो दिन की बिजली कटौती के वक्त जब उत्पादन रुका और छह कारीगरों को खाली बैठा देखा पड़ा तब 'आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है' वाली कहावत सच साबित हुई। मोहिता ने अपने कारीगरों से बचे हुए कपड़ों के टुकड़ों (कतरन) से तुर्की स्टाइल की फैब्रिक ज्वेलरी बनवाई। इस्तेमाल पर पोस्ट करते ही ये पीस रातोंरात बिक गए। इससे ब्रांड का ग्रॉस मार्जिन 15 प्रतिशत तक बढ़ गया।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट, 3 सप्ताह में निकल गए 38 अरब से ज्यादा

मुंबई, एजेंसी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे सप्ताह भारी गिरावट की खबर है। 25 सितंबर 2026 को सप्ताह के दौरान इसमें भी ज्यादा कमी की खबर है। एक सप्ताह में इतनी गिरावट कभी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें करीब 14.881 की गिरावट आई थी। उससे एक सप्ताह पहले मतलब कि 11 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 4.924 निकल गए थे। मतलब कि तीन सप्ताह में ही 38.148 डॉलर निकल गए। हां, 4 सितंबर 2026 तक लगातार 10 सप्ताह इसमें बढ़ोतरी ही हो रही थी।

विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 25 सितंबर 2026



को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 18.343 की कमी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें 14.881 की कमी हुई थी। अब अपना विदेशी मुद्रा भंडार घट कर 747.557 रहा गया है। इससे पहले 4 सितंबर 2026 को अपना विदेशी मुद्रा भंडार 785.706 के ऑल टाइम हाई पर था।

एफसीए भंडार में खूब हुई कमी
रिजर्व बैंक की तरफ से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 25 सितंबर 2026 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा आस्तियों में 15.570 की कमी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें 14.816 की कमी हुई थी। ताजा कमी के बाद अपना एफसीए भंडार घट कर 615.411 का रह गया है। उल्लेखनीय है कि देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा आस्तियां या फॉरेन करेंसी असेट एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। डॉलर में अभिव्यक्त किये जाने वाले विदेशी मुद्रा आस्तियों में यूरो, पौंड और येन जैसे गैर अमेरिकी मुद्राओं में आई घट-बढ़ के प्रभावों को भी शामिल किया जाता है।

आंध्र प्रदेश में तीन लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे पक्के घर

3,600 करोड़ रुपये की मंजूरी

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के बुरिपालेम गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 2.0 के तहत तीन लाख घरों की पहली किस्त सौंपने की शुरुआत की। इन घरों के निर्माण पर 3,600 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस मौके पर उन्होंने देश की पहली 3डी कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक आधारित आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना के तहत 14 करोड़ रुपये की लागत से 177 घर बनाए जाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, आंध्र प्रदेश के लिए पहले 76 हजार घरों का आवंटन प्रस्तावित था। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर तीन लाख घर कर दिया। चौहान ने कहा कि तीन लाख घरों का निर्माण पूरा होने के बाद केंद्र सरकार राज्य के लिए तीन लाख और घर मंजूर करेगी। तीन लाख और घर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के हर गरीब परिवार को पक्का घर



उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। चौहान ने बुरिपालेम और ओबुलनायडुपालेम में 3डी कंक्रीट प्रिंटिंग आधारित आवास परियोजना को ग्रामीण आवास के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ रुपये की इस पायलट परियोजना में आधुनिक मशीनों और 3डी कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। इससे निर्माण समय, लागत और श्रम की जरूरत कम होगी। 177 घरों का निर्माण छह महीने में पूरा होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अमरावती के विकास के लिए भी सहयोग कर रही है। केंद्र ने आंध्र प्रदेश की एकमात्र स्थायी राजधानी के रूप में अमरावती को मान्यता देने के लिए संसद में कानून पारित किया और इसके विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय

सहायता दी है। उन्होंने पोलावरम सिंचाई परियोजना को राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसे केंद्र से 100 प्रतिशत अनुदान सहायता मिल रही है। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र से किसानों को सालाना छह हजार रुपये और आंध्र प्रदेश सरकार की 'अन्नदाता सुखीभव' योजना के तहत 14 हजार रुपये की सहायता मिलाकर किसानों को हर वर्ष 20 हजार रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश फलों, फूलों, सब्जियों और औषधीय फसलों के क्षेत्र में देश का प्रमुख बागवानी केंद्र बन सकता है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 23 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। एनडीए सरकार का लक्ष्य इनकी संख्या बढ़ाकर 60 लाख करना है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय सरस मेला 15 अक्टूबर को पहली बार दिल्ली से बाहर आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इसका उद्घाटन करेंगी। चौहान ने तेलुगु में लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि यदि वह मध्य प्रदेश के 'मामा' हैं तो आंध्र प्रदेश के भी 'मामा' हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा उनके लिए पूजा के समान है।

सैनिक का पार्थिव शरीर लेकर लौट रही एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, पुत्र समेत चार लोगों की मौत

एजेंसी, देवरिया

चंडीगढ़ से सेना के जवान सूबेदार सत्यवान सिंह का पार्थिव शरीर लेकर देवरिया आ रही एंबुलेंस रविवार सुबह सुलतानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एंबुलेंस में सवार जवान के पुत्र राहुल सिंह, रुद्रपुर नगर पंचायत के सभासद राजन चौधरी, उनके छोटे भाई राम सुमित सिंह और चालक जसपाल की मौके पर ही मौत हो गई। एक ही परिवार में पहले जवान की मौत और इसके बाद उनके पुत्र समेत तीन अन्य लोगों की सड़क हादसे में मौत से रुद्रपुर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुःख है। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस के अनुसार, देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के गहिला-दुधैला गांव निवासी सत्यवान सिंह



(50) सेना में जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) के पद पर मेरठ में तैनात थे। शुक्रवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आर्मी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सेना की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर एंबुलेंस से पैतृक गांव रुद्रपुर लाया जा रहा था।

बताया गया कि एंबुलेंस में चालक जसपाल के अलावा सत्यवान सिंह के पुत्र राहुल सिंह, रुद्रपुर नगर पंचायत के सभासद राजन चौधरी और उनके छोटे भाई राम सुमित सिंह सवार थे। रविवार सुबह सुलतानपुर जिले के हलियापुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अचानक एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला युवक गुवाहाटी से गिरफ्तार



एजेंसी, गुवाहाटी

तेजपुर के सेना की गजराज मिलेट्री इंटेलिजेंस (एमआई) से मिली शुरुआती जानकारी के आधार पर, असम के आईजीपी (एसटीएफ) ने शोणितपुर के एसएसपी के साथ मिलकर उस खुफिया जानकारी पर काम किया और उसे गिरफ्तार किया। यह जानकारी अभिषेक कुमार सिंह द्वारा पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव (पीआईओ) के निर्देशों पर कथित तौर पर की जा रही संदिग्ध राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के बारे में थी। इस खुफिया जानकारी के आधार पर, 3 और 4 अक्टूबर की रात को असम एसटीएफ ने एक अभियान चलाया

और अभिषेक कुमार सिंह (31) को गुवाहाटी के सातगांव पुलिस स्टेशन के तहत गांधीनगर में एक किराए के घर से गिरफ्तार किया। वह मूल रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। अभियान के दौरान, उसके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए।

शुरुआती जांच से जासूसी से जुड़ी गतिविधियों में उसकी कथित सलिप्तता का पता चला है, जिसमें सुरक्षा बलों से जुड़ी गुप्त जानकारी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव (पीआईओ) तक पहुंचाना शामिल है। इसके अनुसार, अभिषेक कुमार सिंह को एसटीएफ पीएस केस नंबर 09/2026 के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

राजमार्गों की सुरक्षा व गुणवत्ता पर होगा मंथन, गुजरात के एकता नगर में 5-6 अक्टूबर को चिंतन शिविर

एजेंसी, नई दिल्ली

देश में सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप राजमार्ग अवसंरचना विकसित करने को लेकर केंद्र सरकार 5 और 6 अक्टूबर को गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में 'चिंतन शिविर-2026' आयोजित करेगी। दो दिवसीय शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियां और अन्य हितधारक शामिल होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, शिविर का मुख्य उद्देश्य राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही प्रमुख अड़चनों की पहचान कर उनके व्यावहारिक और नवोन्मेषी समाधान तलाशना है। साथ ही परियोजनाओं की गुणवत्ता, सड़क सुरक्षा, दक्षता और समयबद्धता बढ़ाने के लिए नीतिगत और संस्थागत सुधारों पर भी मंथन होगा।

चिंतन शिविर का उद्घाटन 5 अक्टूबर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इस मौके पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहेंगे। विभिन्न राज्यों के सड़क परिवहन एवं लोक निर्माण मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि और



विशेषज्ञ भी शिविर में भाग लेंगे।

मंत्रालय के अनुसार, शिविर केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। इसमें राज्यों के अनुभव, जमीनी स्तर पर सामने आ रहे व्यावहारिक समाधान और बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा किया जाएगा। इससे राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए साझा रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

दो दिनों के दौरान पांच प्रमुख विषयों पर अलग-अलग सत्र आयोजित होंगे। इनमें प्रधानमंत्री गतिशक्ति और एकीकृत अवसंरचना योजना, भूमि अधिग्रहण एवं भूमि राशि पोर्टल, मॉडल रियायत

नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन, परियोजनाओं की अड़चनों से लेकर भूमि अधिग्रहण तक पांच मुद्दों पर होगी चर्चा

समझौते एवं रेटिंग व्यवस्था, सुरक्षित राजमार्गों की डिजाइनिंग तथा गुणवत्ता आश्वासन एवं परियोजना निगरानी शामिल हैं। प्रधानमंत्री गतिशक्ति सत्र में विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित विकास पर चर्चा होगी। भूमि अधिग्रहण और भूमि राशि से जुड़े सत्र में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली अड़चनों और उनके समाधान पर विचार किया जाएगा। वहीं मॉडल रियायत समझौते एवं रेटिंग व्यवस्था पर संविदात्मक और क्रियान्वयन संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी। सुरक्षित राजमार्गों की डिजाइनिंग से जुड़े सत्र में सड़क सुरक्षा को राजमार्गों की योजना और निर्माण प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनाने पर जोर दिया जाएगा। गुणवत्ता आश्वासन एवं परियोजना निगरानी सत्र में निर्माण की गुणवत्ता, निगरानी तंत्र और परियोजनाओं के बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार होगा। मंत्रालय को उम्मीद है कि चिंतन शिविर से राजमार्ग विकास में नई कार्यप्रणालियों और बेहतर संस्थागत व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

रघुबीर यादव ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी बातें की

'पंचायत' के प्रधान जी यानी रघुबीर यादव हुंकार में बाप जी बनकर दिखाई दे रहे हैं और उनकी आने वाली फिल्म है 'ओम का हरि'। इन सबको लेकर वो खूब चर्चे में हैं। एक्टर ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई सारी बातें की हैं।

बीते सालों में रघुबीर यादव हर रंग की भूमिकाओं में खिले हैं और कभी भी उनके काम पर उंगली नहीं उठी। इस पर वे कहते हैं, 'इतने सालों से मैंने खुद को रियाज से जोड़े रखा है। मेरा ताल्लुक हमेशा से थिएटर से रहा है। मैं जब भी कोई काम करता हूँ, तो सबसे पहले खुद से पूछता हूँ कि मुझे इसे करते हुए अच्छा लग रहा है या नहीं। बस यही कोशिश रहती है कि मेरी नीयत, शिद्दत में और मेरी कोशिश में कोई कमी न रह जाए। मगर परफेक्शन कभी हासिल नहीं होता। प्ले और नाटकों में जरूर कुछ 70-75 प्रतिशत तक पहुंच पाया हूँ।'

उन्होंने आगे कहा, 'एक प्ले बेरी जॉन के साथ किया था, जब मैं एनएसडी रेपर्टरी में था। 'बेगम का तकिया' और 'मुख्यमंत्री' जैसे नाटक में काम करके संतुष्टि मिली थी। थिएटर में आप लगातार काम करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते थे। लेकिन फिल्मों में ऐसा लगता है कि एक बार काम शूट होकर रिलीज हो

गया, तो फिर बस छाती पीटते रहो कि यार, थोड़ा और बेहतर हो सकता था।'

भूखे मर जाना, मगर वैसी फिल्म न करना

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं, 'मैंने हर बार कोशिश की है कि अपनी भूमिका को जमा लूं, अपने रोल के साथ न्याय करूं, मगर एक बार ऐसा जरूर हुआ था कि बात बन नहीं पाई थी। मैं सलाम बॉम्बे जैसी कई अच्छी फिल्में कर चुका था। मगर मैं नया-नया आया था और उसी दौरान गुजारे के लिए मैंने एक फिल्म कर ली। उसमें मेरा कोई खास मोह नहीं था। एक बार किसी फंक्शन से लौटते वक्त एक महिला ने मुझे रोककर कहा, 'आपको शर्म नहीं आती किसी को तकलीफ पहुंचाते हुए?' मैं घबरा गया। मैंने सोचा, मैं तो उस महिला को जानता तक नहीं। वो ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने पूछा क्या हुआ? महिला बोलीं, 'आपको वो फिल्म करने की क्या जरूरत थी?' मैंने कहा, 'मैं नया-नया आया हूँ, घर चलाने के लिए काम तो करना है।'

उन्होंने कहा, 'आप भूखे मर जाएं, लेकिन इस तरह की फिल्म मत कीजिए।' उनकी बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभा गई। मैंने कान पकड़ कर कहा, आज से मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन ऐसी फिल्म दोबारा नहीं करूंगा।'

रघुबीर की हालिया फिल्म हरी का ओम पिता -पुत्र के बीच जनरेशन